Dia Mirza Asks For Written Apology...

Ranchi ● Wednesday, 26 March 2025 ● Year : 03 ● Issue : 70 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सेहरी (गुरुवार) : 04:28

: 78,017.19 निफ्टी : 23,668.65

110.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

OBRIEF NEWS 12 हजार रुपये घूस लेते मनरेगा बीपीओ अरेस्ट

PLAMU: मंगलवार को गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के मनरेगा बीपीओ प्रभु कुमार को 12 हजार रिश्वत लेते पलामू प्रमंडलीय एसीबी की टीम ने मंगलवार को रंगेहाथ अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम बीपीओ को लेकर मेदनीनगर पहुंची और जरूरी प्रक्रिया पुरी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू के पुलिस अधीक्षक के अनुसार रमना के हरदाकला के शिव शंकर राम की माता जीतनी देवी के नाम से डोभा का निर्माण कार्य मिला था। इस योजना को चालु करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए जब शिव शंकर बीपीओ से मिले तो उन्होंने 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

दिल्ली में एक लाख करोड रुपये का बजट पेश

NEW DELHI: मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में यह 31.5 फीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि सरकार को 68,700 करोड़ रुपये कर से प्राप्त होगा। वहीं ७५० करोड़ रुपये कर के अतिरिक्त कमाई से, 15 हजार करोड़ रुपये लघु अवधि कर्ज से और 1 हजार करोड़ रुपये सडक निधि से आएंगे। इसके अलावा ४१२८ हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार की योजनाओं से आएंगे और 7,341 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मदद के रूप में लिए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 21 हजार रुपये दिए जाएंगे।

मणिपुर : तलाशी अभियान में मिले हथियार-विस्फोटक

IMPHAL: मंगलवार को मणिपर में सुरक्षा बलों ने विभिन्न संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर हथियार और विस्फोटक बरामद किए। पुलिस प्रवक्ता ने आज बताया कि चुराचांदपुर जिले में डांपी रिज के तलहटी में स्थित माओजांग और डांपी गांवों के पास अभियान के दौरान एक एके-47 राइफल, एक .303 राइफल, एक 12 बोर राइफल, एक डबल बैरल राइफल, एक मॉडिफाइड एसकेएस राइफल, दो लॉन्ग रेंज मोर्टार, दो नंबर 36 हैंड ग्रेनेड, 11 कारतूस, तीन पाइप बम, दो हेलमेट, एक बुलेटप्रूफ जैकेट कवर और एक वॉकी-टॉकी बरामद किया गया।

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर विस में हुआ जोरदार हंगामा मंगलवार को झारखंड विधानसभा के

बजट सत्र के 18वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली का मुद्दा देर तक गूंजता रहा। अल्पसूचित प्रश्न के जरिए हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने मामला उढाया। सरकार से पूछा कि निजी स्कूल की फीस कितना हो, इसके

लिए क्यों नहीं कानून बनना चाहिए। प्रदीप ने कहा कि कोई ऐसा स्कूल नहीं, जो री-एडमिशन के नाम पर पैसे की वसुली नहीं करता है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या राज्य में संचालित एक ही बोर्ड के समस्त निजी स्कलों में सरकार एक समान शुल्क निर्धारित करने का अधिकार रखती है।

जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने

ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ

कार्रवाई करने की बात कही है।

अल्पसूचित प्रश्न के जरिए विधायक प्रदीप प्रसाद ने उठाया मामला री-एडमिशन के नाम पर पैसे लेने व विसंगतियों पर बने कानून : स्पीकर



उपायुक्त को करनी चाहिए हर माह बैठक : बाबूलाल

री-एडमिशन के मनमाना शुल्क वसलने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि यह विषय काफी गंभीर है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर

न्यायाधिकरण बना हुआ है, लेकिन इसके लिए जो बैठकें होनी चाहिए. वह नहीं होती है। उपायुक्त को कम से कम हर महीने कमेटी की बैठक

जिला स्तर की कमेटी में करें शिकायत : रामदास

विधायक नवीन जयसवाल ने निजी विद्यालयों द्वारा मनमाना ढंग से ली जाने वाली री-एडमिशन शुल्क पर रोक लगाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि अगर कोई भी निजी स्कूल री-एडिमशन के नाम पर कोई शुल्क ले रहा है तो जिला स्तर की कमेटी में इसकी शिकायत करें। उन्होंने ऐसा करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही है। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने भी मनामाना ढंग से ली जानी वाली फीस पर रोक लगाने का समर्थन किया।

एमएलए जयराम महतो ने निजी कंपनियों में 75 फीसद आरक्षण का उठाया मुद्दा

जयराम महतो ने निजी कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण का मुद्दा उढाया। निजी कंपनियों में दो लाख गैर झारखंडी हैं,



जायसवाल ने भी पूछा कि आउटसोर्सिंग कंपनी को निजी कंपनी मानते हैं या नहीं। ऐसी क्या पॉलिसी बनाएंगे कि झारखंड के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण मिल सके। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि कानून रातों रात लागू नहीं हो

पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की उठी मांग

डीजीपी नियुक्ति मामले में सीएस सहित अन्य

प्रतिवादियों को नोटिस

सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक प्रदीप यादव ने पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गढन की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्ग की संख्या 90 प्रतिशत से भी अधिक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढाते हए

सकता। हाईकोर्ट के आदेश से पहले कंपनियां आरक्षण का पालन कर रही थीं। आउटसोर्सिंग निजी कंपनी ही है। मंत्री

PHOTON NEWS RANCHI:

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने

पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय अब तक प्रभावी नहीं हो पाया है। उन्होंने संविधान के 93वें संशोधन (शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और हाई कोर्ट के निर्णय का भी जिक्र किया, जो राज्य में लागू नहीं हो पाया है।

संजय प्रसाद यादव ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी निजी कंपनी ही मानी जाती है।

• सुप्रीम कोर्ट में 4–5 मई

को होगी इस मामले की

अगली सुनवाई

• बाबूलाल मरांडी ने

है प्रतिवादी

अपनी याचिका में इन

अधिकारियों को बनाया

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का

अवमानना याचिका दायर की थी।

मामले से संबंधित मूल याचिका

में कई डीजीपी की नियुक्तियों के

संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निदेशों

का उल्लंघन करने से जर्ड

अनेक याचिकाएं दायर की गयी

थीं। हालांकि सभी याचिकाओं

को 25 के लिए सचीबद्ध नहीं

किया गया था। इसलिए न्यायालय

ने सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध

उल्लंघन करार देते

हेमंत कैबिनेट का फैसला : मीटिंग में १६ प्रस्तावों पर लगी मुहर

सिंगल बैंक खाताधारी को ही मिलेगा मंईयां योजना का लाभ

मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत मार्च-2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार) को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। मनरेगा योजना के तहत जेटोफा पौधा में गडबडी करने वाली राज्य सेवा की बर्खास्त करने का फैसला लिया अफसर साधना जयपरियार को गया। वर्तमान में वह निलंबित थीं।

झारखंड सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक को मिली स्वीकृति

राज्य सेवा की अफसर साधना जयपुरियार को किया गया बर्खास्त

इन प्रस्तावों को

हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड

सक्ष्म, लघ एवं मध्यम उद्यम (विशेष

छूट) विधेयक-२०२५ के गढन की

स्वीकृति दी है। इसके साथ ही

वित्तीय वर्ष २०२४–२५ के तृतीय

स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष

2025-26 के बजट प्राक्कलन पर

कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी

गई है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण

2024-25 को विधानसभा के पटल

पर पेश करने के संबंध में घटनोत्तर

स्वीकृति दी गई।

अनुपुरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर

भी मिली स्वीकृति

■ वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुपूरक बजट को घटनोतर दी गई स्वीकृति

 आर्थिक सर्वेक्षण और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को घटनोतर मंजूरी

छह कर्मियों की सेवा होगी नियमित

हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक (18.08.2022) में की गई अनुशंसा के आलोक में कुल छह कर्मियों की सेवा संपष्टि/नियर्मितीकरण करने की स्वीकित दी गई। झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की

कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में संबंधित प्रावधान को सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

अब जेल का रख-रखाव देखेगा भवन निर्माण विभाग

झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब जेल का रख-रखाव भवन निर्माण विभाग करेगा। पेयजलापूर्ति का काम पेयजल विभाग करेगा। जलसंसाधन विभाग में निर्माण कार्य श्रेणी में 18 जुलाई 2022 से प्रभावी डीएसटी दर में 12 से 18 फीसदी की वृद्धि के परिपेक्ष्य में कार्यसंविदा से संबंधित भुगतान राशि की अंतरदेयता की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में इंटर स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 2399 पद और स्नातक स्तर के सहायक आचार्य के 1052 पद सहित कुल 3421 पद कर्णांकित करने की स्वीकृति दी गई।

डीजीपी के पद पर नियुक्ति से संबंधित एक अवमानना याचिका में प्रतिवादी बनाए गए अधिकारियों को नोटिस जारी

करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए चार-पांच मई की तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। बाबलाल मरांडी ने अपनी याचिका में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रतनाकर भेंगरा और नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया है। सप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश संजय कमार और

एनडीपीएस के स्पेशल जज ने खारिज की अभियुक्त रामसेवक की याचिका

ड्रग की तस्करी के खतरे से सख्ती से निपटना जरूरी

मंगलवार को एनडीपीएस के विशेष

न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने अभियुक्त रामसेवक कम्हार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इंग के इस्तेमाल और इसकी तस्करी के खतरों से सख्ती से निपटना चाहिए। पांडेय ने इसके साथ ही अभियुक्त की मिसलेनियस क्रिमनल पीटिशन को निष्पादित कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4348.80 किलो डोडा जब्त करने से जुड़े मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। वह फरवरी 2025 से जेल में है। अभियुक्त की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह डोडा जब्त करने से जड़ी प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है।

४३४८.८० किलो डोडा जब्ती मामले में अभियुक्त को किया गया था अरेस्ट

मामले में नरमी से विचार करना चाहिए।

सरकारी वकील ने अभियुक्त की ओर

विरोध किया। साथ ही यह भी कहा कि

उसे 4348.80 किलो डोडा के मामले में

गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ

नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

से दी गई दलील और अनुरोध का

व्यवहार न्यायालय, राँची CIVIL COURTS, RANCHI

अभियुक्त की ओर से दी गई दलील का विरोध

डोडा के साथ गिरफ्तार लोगों ने उसका नाम भी नहीं लिया था। उसके पास से कुछ बरामद भी नहीं किया गया है। टीआई परेड में उसकी पहचान भी नहीं कराई गई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। इन तथ्यों के देखते हुए न्यायालय को अभियुक्त के

बाद जज ने दिया फैसला सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले से संबंधित दस्तावेज की जांच में पाया कि

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 23 नवंबर 2024 को रांची टाटा मार्ग पर लाइन होटल के पास एक ट्रक को पकडा था। इसमें ४३४८ ८० किलो डोडा पाया गया था। ट्रक के साथ पकडे गए लोगों के पास इससे संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। इसलिए टक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया था।

सभी पक्षों को सुनने के

का डनामी सधाकर सहित ३ नक्सली ढेर

DANTEWADA: मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर-नारायणपर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुंटभेड़ में 25 लाख के इनामी सुधीर उर्फ बंतेवाड़ा-

सुंधाकर सहित बीजापुर-नारायणपुर जिले की सरहद पर पुलिस और के बीच एनकाउंटर

आईजी सुंदरराज पी. ने की तीन नक्सिलयों

पुष्टि की है। बस्तर आईजी की पुष्टि बीजापुर

क्षेत्रान्तर्गत थाना गीदम के ग्राम गिरसापारा, नेलगोडा, बोडगा तथा इकेली के सरहदी क्षेत्र में नक्सल कैडरों की उपस्थिति के सुचना पर नक्सल विरोधी अभियान पर दंतेवाडा डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम अभियान पर रवाना हुई थी। इस अभियान के दौरान आज सुबह 8 बजे से नक्सिलयों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ हो गई। इसके बाद तलाशी अभियान में मौके से 3 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद



आईजी बस्तर

के मारे जाने

किए गए।



3 नक्सली ढेर हए हैं। इसके साथ मारे गए दो अन्य नक्सलियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं ' बस्तर सुन्दरराज पी. ने तीन

नक्सिलयों के मारे जाने की

सुंदरराज पी. ने बताया कि जिला दंतेवाड़ा और

ने अनराग गप्ता को डीजीपी के करते हुए चार-पांच मई को पद पर नियक्ति को प्रकाश सिंह अगली सनवाई की तिथि निर्धारित बनाम केंद्र सरकार मामले में करने का निर्देश दिया।

संजीव खन्ना,

न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की

पीठ में इस मामले की सुनवाई

हई। भाजपा नेता बाबलाल मरांडी

सुप्राम काट के फसला का उल्लंघन

बाबूलाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त करने के दौरान प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिये गये फैसलों और दिशा-निदेशों का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को दिए अपने आदेश में यह कहा था कि राज्य सरकार डीजीपी के पद पर प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों की सूची लोक सेवा आयोग को भेजेगी। आयोग द्वारा तैयार पैनल में से सरकार किसी को डीजीपी के पद पर नियुक्त करेगी। नियुक्ति की तिथि से

डीजीपी का कार्यकाल दो साल के लिए होगा, भले ही उसके सेवानिवृति की तिथि पहले हो। डीजीपी की नियुक्ति पुरी तरह मेरिट के आधार पर होगी। इसमें किसी तरह का दबाव या प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याचिका में बताया गया है कि न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि डीजीपी के पद पर नियुक्त अधिकारी को निर्धारित समय सीमा से पहले तभी हटाया जाएगा, जब उसके खिलाफ अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत किसी कार्रवाई का निर्णय लिया गया हो या किसी न्यायालय द्वारा उसे किसी आपराधिक या भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया हो।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला

आईआरबी, होमगार्ड और असम राइफल के 7 जवान सहित 8 अरेस्ट

PHOTON NEWS RANCHI: जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक 2024

मामले में झारखंड सीआईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजीपी के आदेश पर सीआईडी की टीम ने इस मामले में शामिल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पांच आईआरबी के जवान हैं। इनमें कुंदन कुमार, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार अभिलाष कुमार शामिल हैं। इसके अलावा एक असम राइफल का जवान राम निवास राय और एक होमगार्ड जवान निवास कुमार राय के अलावा एक अन्य व्यक्ति कविराज शामिल है। गौरतलब है कि 21 और 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलो में परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। सीजीएल पेपर में कथित धोखाधड़ी और सीजीएल परीक्षा के उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी और



से पैसे मांगने का मामला

दिग्भ्रमित करके प्रश्नपत्र देने के नाम पर धन उगाही का मामला सामने आया था। सीआईडी को अनुसंधान के क्रम में पता चला कि परीक्षा के पूर्व ही एक गिरोह के सदस्य द्वारा अभ्यार्थियों को सीजीएल पेपर के प्रश्नों को देने के नाम पर धन उगाही की गई है। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस गिरोह का तथाकथित सरगना गोरखपुर का निवासी है।

क्रांतिकारी उपलब्धि तमिलनाडु में 2500 हाथियों का कुशलता से किया गया बचाव

पशु सुरक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही एआई टेक्नोलॉजी

आज के दौर में सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का कमाल दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी यही बात है। अगर सकारात्मक पहलू के रूप में इसकी उपलब्धियां सामने दिख रही है, तो नकारात्मक पहलू को लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है। हमें यह देखना होगा कि जब एक बार कोई तकनीक डेवलप कर जाती है, तो इसके नकारात्मक पहलुओं के कारण इसे अचानक बंद नहीं कर दिया जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी यही बात सही है। हाल में यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि जंगलों में पशु सुरक्षा के क्षेत्र में यह टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रही है। भारत में इसका असर देखा गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यहां हाथियों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)

तकनीक बेहद प्रभावी साबित हुई है।

कोयंबटूर के मदुक्कराई वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है यह सिक्योरिटी सिस्टम पिछले साल फरवरी में इस प्रणाली को विभाग की ओर से किया गया था शुरू हाथियों ने सुरक्षित पार किया ट्रैक हाथियों को

सप्ताह में पूरी प्रणाली की समीक्षा के बाद पता चला इसका प्रभाव सिस्टम के माध्यम से अब तक जारी किए गए हैं 5011 अलर्ट इस प्रणाली के तहत ए इस सिस्टम के तहत ए और बी रेलवे ट्रैक पर 12 ई-निगरानी टावर और बी रेलवे ट्रैक पर लगे हैं। इनमें हाई रिजाल्यशन

लगाए गए हैं 12 ई-

निगरानी टावर

तुरंत एक्टिव हो जाते हैं विभागीय कर्मचारी

कैमरे लगे हैं। यह लगभग एक

किमी क्षेत्र कवर करते हैं और 360

डिग्री घूम सकते हैं। कैमरे हाथियों

टैक करते हैं कैमरे और नियंत्रण कक्ष को लगातार भेजते

को ट्रैक करते हैं और नियंत्रण कक्ष को अलर्ट भेजते हैं। वन विभाग के गश्ती ढल और रेलवे लोको पायलट को अलर्ट मिलते ही एक्टिव हो जाते हैं और हाथियों को सुरक्षित ट्रेक पार कराते हैं।

अनुसार, कोयंबदूर के मदुक्कराई वन क्षेत्र में स्थापित एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने अब तक 2500 से अधिक जंगली हाथियों को बचाने में सहायता पहुंचाई है। एआई प्रणाली केवल हाथियों की निगरानी के लिए ही नहीं, बल्कि जंगलों में

राज्य के पर्यावरण, जलवायु

परिवर्तन और वन विभाग के

हुई थी। मार्च २०२५ के चौथे सप्ताह में इसकी समीक्षा की गई। इसमें यह सामने आया होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। एक कैमरा 300 मीटर के क्षेत्र प्रदान की।

कि यह प्रणाली लगातार प्रभावी रूप से काम कर रही है। २५०० हाथियों को सुरक्षित ट्रैक पार करने में सहायता

की निगरानी कर रहा है, जहां

जंगली हाथियों की आवाजाही

अक्सर होती है। वन विभाग

की ओर से जानकारी दी गई

है कि इस परियोजना की

शुरूआत फरवरी 2024 में

हत्या के दोषी को

आजीवन कारावास

अदालत ने मंगलवार को दंपति के बीच हो रही मारपीट को सुलझाने गए बेंजामिन

दुडू को मौत के घाट उतारने वाले आरोपित संदीप दुडू को दोषी पाते हुए अदालत ने

राशन में सोयाबीन का भी रखा प्रस्ताव : उरांव



LOHARDAGA: खाद्य, सार्वजनिक, वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर मंगलवार को नया नगर भवन में जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीबों की संख्या काफी अधिक थी जिन्हें राशन नहीं मिलता था। कई परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजनाओं में नहीं था। केंद्र सरकार लाल और पीला राशन कार्ड से राशन दे रही थी लेकिन अब तक कई परिवार वंचित थे। वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल में मैंने बतौर विभागीय मंत्री रहते हुए हरा राशन कार्ड की योजना लायी जिससे छूटे हुए परिवार अच्छादित हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलो अनाज मिलता है। देश में अधिकतर राज्यों में सिर्फ अनाज दिया जाता है जबिक झारखंड में चावल, गेहूं, चना दाल भी दिया जाता है। मैंने सरकार को प्रति परिवार को सोयाबीन दिये जाने का भी प्रस्ताव दिया है। अगर यह योजना लाग हो जाती है तो प्रत्येक परिवार को चावल, गेहुं, दाल और सोयाबीन के रूप में एक सब्जी मिल सकेगी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजद थे।

अष्ट्रप्रहर हरिनाम संकीर्तन का समापन

GHATSILA: प्रखंड के कालचित्ती पंचायत अंतर्गत हीरागंज स्थित हरि मंदिर प्रांगण केंदडांगा मे दिध उत्सव के साथ अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन का समापन मंगलवार को हो गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू शामिल हुईं। इस मौके पर कला दास वरण संप्रदाय माटियाबांधी, शिव शंकर सिंह संप्रदाय बांदवान, आंचलिक संप्रदाय पुरुलिया, शुभांकर संप्रदाय शुकलाड़ा मानगो, जय राधे संप्रदाय सिंहपुरा व गोविंद कामारी महिला संकीर्तन संप्रदाय गोपीबल्लभपुर की कीर्तन

पंचमुखी हनुमान की हुई प्राण-प्रतिष्ठा



KHUNTI: खुंटी बड़ाईक टोली में नवनिर्मित श्रीश्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंगलवार को भक्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर में सुबह भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। शहर के पुरातन महादेव मंडा से बाजे-गाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में 251 मंगल कलशों को शिरोधार्य कर महिलाएं और युवतियां भजनों की धुन पर पथ संचलन कर रही थीं। इनके अलावा केंद्रीय रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष अनुप साहु, महामंत्री जितेंद्र कश्यप, ज्योतिष भगत, कुमार ब्रजिकशोर समेत बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु महिला-पुरुष और बच्चे कलश यात्रा में शामिल होकर ताशा की धुन पर जयकारा लगाते चल रहे थे।

पुलिस ने 60 लाख की स्प्रिट व शराब के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

बिहार की सीमा से सटे महुवरी गांव में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा

पलामु जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और नौडीहा बाजार थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिहार सीमा से सटे महुवरी गांव में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। यहां से टीम ने 45 लाख रुपए कीमत का 22 हजार लीटर स्प्रिट बरामद किया है । साथ ही 15 लाख रुपये की नकली अंग्रेजी शराब भी जब्त की है। पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान मकान मालिक महुवरी के धीरज सिंह और बिहार के समस्तीपर बिहार के राजा कुमार पांडेय के रूप में हुई है। बिहार के कुटुम्बा थाना के करमडीह के संतोष कमार की



बरामद शराब के साथ पुलिस पदाधिकारी

संजीत कमार देव ने मंगलवार को बताया कि शराब फैक्ट्री एक

यह मकान धीरज सिंह का बताया जा रहा है। सोमवार रात से सबह से 550 गैलन स्प्रिट बरामद किया।

पिकअप में लदी 150 पेटी नकली

करने का निर्देश दिया। त्योहारों के

दौरान किसी भी दुर्घटना की स्थिति

पर स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रखंडों

के स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील

अवस्था में रखने का निर्देश सिविल

सर्जन को दिया तथा जुलूस के दौरान

मेडिकल कैंप को सक्रिय रखने को

भी कहा।नगर निगम क्षेत्रो में की

साफ सफाई, जुलूस मार्गी में पड़ने

वाले शौचालय को क्रियाशील रखने

सहित पेयजल वालो स्थानों को

दुरुस्त करने का निर्देश दिया। हर वर्ष

की तरह इस वर्ष भी जुलूस मार्गों में

लोहे की बैरिकेटिंग की व्यवस्था

करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त

ने रिस्पांस टाइम, कम्युनिकेशन

प्लान,मेडिकल प्लान आदि को

दुरुस्त करते हुए अपनी तैयारीयों को

मुकम्मल रखने का निर्देश दिया।

शामिल हैं। एक गैलन में 40 लीटर स्प्रिट होता है, जिसकी कीमत लगभग 8 हजार रुपए है। जानकारी के अनुसार, यह अवैध धंधा पिछले दो साल से लोकेशन बदल-बदलकर चल रहा था। बरामद स्प्रिट और शराब की कीमत लगभग 60 लाख से अधिक होगी। उत्पाद विभाग की टीम अब जांच कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि नकली शराब कहां-कहां सप्लाई की जाती थी। छापेमारी में उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव, एसआई अमीत कुमार सिंह, थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी, एएसआई संजय कुमार

आजीवन कारावास की सजा सुनायी है साथ ही अथालत ने 10 हजार रुपय जुमार्ना भी लगाया है। जुमार्ना की राशि अँदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना नौ साल पूर्व तीन अक्टूबर 16 को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिरसा गांव की है। इस घटना में सरकार की ओर से एपीपी धनंजय साह और बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसी सिकंदर मंडल ने बहस की। अदालत ने 12 गवाह के बयान और सबत के आधार पर यह सजा सनाई। पुलिस को दिए बयान में मृतक के बड़े भाई सामुएल टुडू ने बताया कि तीन अक्टूबर 20 16 की सुबह भाई बेंजामिन गांव के संदीप एवं उसकी पत्नी नीलू हेम्ब्रम से झगड़ा चल रहा था। पति के हाथ में हंसुअ था। भाई बेंजामिन पहाड़िया विद्यालय में काम करने गया था। लेकिन काम बंद होने रास्ते में संदीप के घर के पास से गुजर रहा था। नीलू ने मदद के लिए बेंजामिन को बुलाया। जब बेंजामिन दोनों को शांत कराने का प्रयास कर रहा था, तभी गांव की चार पांच महिलाएं भी पहुंची। इसके बाद संदीप भड़क गया और हरसआ लेकर



सभी को दौड़ाने लगा। महिलाएं तो भाग

गई, लेकिन संदीप ने भाई बेंजामिन के

चाईबासा में बिखर रही पूर्वोत्तर भारत की कला व संस्कृति

CHAIBASA: पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र (ईजेसीसी) संस्कृति केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित ऑक्टेव-25 मंगलवार को आरंभ हुआ। सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में इस उत्सव का उद्घाटन कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी व कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने किया। तीन दिवसीय आयोजन में पूर्वोत्तर भारत के कलाकार अपनी कला-संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर के राज्यों में असम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम पारंपरिक नृत्य शैली और संगीत कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन 27मार्च तक चलेगा। रंगारंग कार्यक्रम के बीच पूर्वोत्तर के कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों से खब तालियां बटोरीं।

रामनवमी पर डीजे व भड़काऊ गानों पर रहेगा प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

जुलूस मार्ग के सभी घरों की छत से हटाएं ईंट-पत्थर, ड्रोन से करें निगरानी : एसपी

रामनवमी को लेकर प्रशासनिक तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें रामनवमी जुलूस के रूट तथा विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी त्योहार को सफल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जुलूस के दौरान वीडियोग्राफी, सीसीटीवी की निगरानी, क्या करें क्या न करें का बैनर लगाने आदि की बात कही। उन्होंने कहा जुलूस के दौरान डीजे व भड़काऊ गानों पर पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान

बजने वाले गानों का पूर्ण



विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य

चुस्त दुरुस्त रहने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल विभाग को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति को पड़ने वाले खराब चापानलो का आकलन करते हुए मरम्मती कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। वहीं बिजली विभाग को पावर कट, शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली आपूर्ति,

• फोटोन न्यूज

यत्र तत्र झलते तारो को व्यवस्थित

लक्ष्य निर्धारित कर सही मार्गदर्शन में आगे बढें छात्र : प्रो. किड़ो

मंगलवार को इंटर के विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कॉलेज की प्राचार्या जेरमेन कुल्लू किड़ो के प्रयास से इसका आयोजन हुआ। प्राचार्या ने कहा कि विद्यार्थियों को पहले लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। सिर्फ नौकरी नहीं, इसके इत्तर भी बहुत से करियर के विकल्प हैं। उनकी जानकारी लेकर करियर बना सकते हैं। कॉलेज की मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर पूनम माई तियु ने कहा कि परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए थोडा टेंशन रहना चाहिए, लेकिन परीक्षा को लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार लम्बे समय तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बीच –बीच में पढ़ाई करते समय थोड़ा विराम लेते रहना चाहिए। उन्होंने तनाव से बाहर निकलने के उपाय भी सुझाये। नागपुरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. कोरनेलियुस मिंज ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए गरीबी बाधक नहीं बनती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण तथा आत्मानुशासन से मंजिल को पाया जा

हजारीबाग जिले में स्थापित होगी कृषक पाटशाला, एजेंसी का किया गया चयन

PHOTON NEWS HAZARIBAG: उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में जिला अनुश्रवण (डीएलएमसी) की बैठक हुई। इसमें जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि हजारीबाग जिले में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की स्थापना की योजना प्रारंभ की गयी है। प्रथम चरण में बीज गुणन प्रक्षेत्र, बडकागांव के लिए राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, हजारीबाग। द्वितीय चरण में बीज गणन प्रक्षेत्र, बरही, बरसोत के लिए छोटानागपुर विकास मंच, हजारीबाग एवं तृतीय चरण में बीज गुणन प्रक्षेत्र, चरही, हजारीबाग के लिए समर्पण चेरिटेबल ट्रस्ट रांची, बीज गुणन प्रक्षेत्र,



बैठक में दिशा-निर्देश देतीं उपायुक्त नैन्सी सहाय

• फोटोन न्यूज

कटकमसांडी के लिए माइनॉरिटी समग्र विकास पुनदाग, रांची एवं बीज गुणन प्रक्षेत्र, नवादा विष्णुगढ़ के लिए अमर संस्कार कल्याण केंद्र, बोकारो का विभाग द्वारा चयन किया गया है। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इन संस्थानों द्वारा कषक पाठशाला के माध्यम से आधनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रत्यक्षण आयोजित किया जाना है। इसके अतिरिक्त कषक पाठशाला के समीप के लगभग 10 गांवों में किसानों को कृषि एवं संबद्ध विषयों पर किसानों को प्रशिक्षित कर खेती

में दक्ष बनाना है तथा कषक पाठशाला में नकदी फसल लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन कर आर्थिक उत्थान के तरफ एक प्रभावी कदम उठाना है। कृषि एवं सम्बद्ध लघु निर्माण यथा बकरी शेड, गाय शेड आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल हजारीबाग एवं कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, हजारीबाग को प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण के लिए नामित किया

अमलगम स्टील कंपनी की मुश्किलें बढ़ीं, रैयत ने शुरू की प्रवेश मार्ग की खोदाई, वाहनों का आवागमन बंद

लीज अवधि समाप्त होने के बाद जमीन मालिक ने उठाया कठोर कदम

सरायकेला-खरसावां जिला के कांड्रा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड और अमलगम स्टील प्राइवेट लिमिटेड की मश्किलें अब और बढ़ गई हैं। स्थानीय रैयत मनसाराम महतो ने कंपनी के प्रवेश मार्ग की खोदाई शुरू कर दी है। इस वजह से कंपनी में वाहनों का प्रवेश और निकासी बंद है। यह विवाद इलाके में चर्चा का विषय बन हुआ है। मनसाराम महतो का कहना है कि यह उनकी रैयती जमीन है। उन्होंने दो साल पहले यह जमीन सशर्त लीज पर दी थी, लेकिन अब लीज की अवधि समाप्त हो गई है। जब उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो



पोकलेन से सडक की खोदाई के दौरान उपस्थित जमीन मालिक व अन्य

और सरक्षा अधिकारी तारकनाथ तिवारी ने उन्हें झुठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। मनसाराम महतो ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित विभागों के अधिकारियों से पत्राचार किया। बावजद कोई समाधान नहीं निकला। अंत में, 21 मार्च को उन्होंने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक,

अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को सूचित कर अपनी पुश्तैनी रैयती जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी का मार्ग अवरुद्ध होने की सचना मिलते ही थाना प्रभारी विनोद मुर्मू मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद मनसाराम महतो अपनी मांग पर

रखा। उन्होंने कहा कि जब तक तेजपाल सिंह और तारकनाथ तिवारी को कंपनी से नहीं हटाया जाता, तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। कंपनी की प्रतिक्रिया, हजारों

रोजगार पर खतरा : कंपनी के अधिकारी तेजपाल सिंह ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से कंपनी चल रही है। कंपनी ने तीन हजार लोगों को रोजगार दिया है। मनसाराम महतो को लीज के अनसार भगतान किया जा रहा था और अब भी उनका चेक तैयार है। हालांकि, मनसाराम महतो अपने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई थी।

भारतीय उपमहाद्वीप में कुर्ता-पजामा पहनने की परंपरा रही है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, ईद के दिन इत्र लगाना, साफ-सुथरे कपड़े पहनना और अच्छे से तैयार होना 'सुन्नत' (पैगंबर मुहम्मद की परंपरा) माना जाता है। ईद पर विशेष नमाज के दौरान ज्यादातर मुस्लिम पुरुष कुर्ता-पायजामा पहनते हैं। यही वजह है कि बाजारों में इस पारंपरिक लिबास के विभिन्न डिजाइन और किस्में उपलब्ध हैं। आम तौर पर लोग कपड़ा खरीदकर अपने नाप के अनुसार कुर्ता-पायजामा सिलवाना पसंद करते हैं, लेकिन मांग अधिक होने की वजह से अधिकतर दर्जियों ने नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। इसलिए लोग अब सिले-सिलाए (रेडीमेड) कुर्ते-पायजामे भी खरीद रहे हैं।

सुन्नत माना जाता है कुर्ता-पाजामा पहनना

दर्जी अब नहीं ले रहे नया आर्डर

मानगो के जवाहर नगर में टेलरिंग की दुकान चलाने वाले मोहम्मद अकरम का कहना है कि समय कम होने की वजह से वह अब नए ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। अकरम ने कहा, हमें ईद से दो दिन पहले तक सभी ऑर्डर पूरे करने हैं, क्योंकि हमें और हमारे कारीगरों को भी ईद मनानी है। हालांकि, जुगसलाई इलाके में टेलरिंग की दुकान चलाने वाले मोहम्मद हनीफ अभी भी नए ऑर्डर ले रहे हैं। हनीफ ने सात अतिरिक्त कारीगरों को काम पर लगाया है और वे 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक कुर्ता-पायजामा सिलने में करीब तीन घंटे का वक्त

केवाईसी नहीं कराने वाले का राशनकार्ड से हटेगा नाम



जागरूकता रथ को रवाना करते उपायुक्त शशि रंजन

• फोटोन न्यूज

PALAMU: खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत ई-केवाईसी जरूरी है। ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित है। सभी गुलाबी एवं पीला राशनकार्डधारी लाभुक अपने नजदीकी डीलर से ई-केवाईसी करा लें। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशनकार्ड से विलोपित किया जाएगा। उक्त बातें पलाम् उपायुक्त शशि रंजन ने कही। वे मंगलवार को समाहरणालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। मौके पर आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू सहित अन्य उपस्थित थे। आपूर्ति विभाग की ओर से पांच जागरूकता रथ का परिचालन किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाये जाने के बाद से जागरूकता रथ के माध्यम से खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न-सामग्री की जानकारी दी जा रही है।

31 मार्च या एक अप्रैल को पड़ेगी ईद, लोगों ने शुरू कर दी जश्न की तैयारी, बाजार में उमड़ रही भीड़

ईद से पहले बाजार में सलमान खान के 'सिकंदर' वाले जोहरा-जबीं कुर्ते की धूम

MUJTABA RIZVI @ JSR:

कंपनी के अधिकारी तेजपाल सिंह

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' कुछ दिन बाद सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन इस फिल्म के मशहूर गाने 'जोहरा जबीं' में उनका पहनावा काले रंग का कुर्ता-पायजामा ईद से पहले युवाओं के बीच खासा धूम मचा रहा है। मुस्लिम युवाओं में, गले से लेकर कंधों और पीछे के ऊपरी हिस्से पर चमकीले रंग की शानदार कढ़ाई वाला, इस तरह का कुर्ता पहनकर ईद मनाने की एक तरह से होड़ लगी हुई है। इस बार ईद का त्योहार 31 मार्च या एक अप्रैल को पड़ सकता है। इसका फैसला चांद दिखाई देने पर होगा। सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 30 मार्च को रिलीज हो रही है। साकची के एक दुकानदार मोहम्मद वसीम ने बताया कि सलमान खान ने 'सिकंदर' में जो काले रंग का कुर्ता-पायजामा पहना है, वैसा ही कपड़ा हाल ही में बाजार में आया है और युवाओं ने इसे हाथों-हाथ लिया है।



१००० से २८०० रूपये तक में बिक रहे कुर्ते

उन्होंने बताया, कि इसकी कीमत सामान्य कुर्ते-पायजामे वाले कपड़ों से अधिक है। वसीम के मुताबिक, जहां सामान्य कढ़ाई वाले कुर्ते-पायजामे १,००० से १,५०० रुपये में मिल जाते हैं, वहीं इस काले रंग के कपड़े की कीमत २,८०० रुपये तक है। मानगो के जवाहर नगर इलाके के एक अन्य दुकानदार मोहम्मद सलमान बताते हैं कि अभिनेता द्वारा पहने गए परिधान के अलावा, बाजार में पाकिस्तानी कढ़ाई वाले कुर्ते–पायजामे का कपड़ा भी अधिक बिक रहा है। उन्होंने बताया कि यह कपड़ा गुजरात के सूरत में ही बनता है, लेकिन अपनी कढ़ाई के कारण इसे 'पाकिस्तानी' नाम से जाना जाता है। इसकी कीमत 1,000-1,500 रुपये के बीच है और यह कई रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है।

कुर्ता-पायजामा की ऑनलाइन बिक्री भी बढ़ी

बिष्टुपुर में रेडीमेड कुर्ते–पायजामे का ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार क्रने वाले एक दुर्कानदार ने कहा कि उन्हें रोजाना 120 से अधिक ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं, जबिक ऑफलाइनू बिक्री 60–65 कुर्ते–पायजामों की हो रही है | उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मांग पाकिस्तानी स्टाइल के कुर्ते-पायजामें की है, जिसकी कीमत 1,500 रुपये से शुरू होती है। कढ़ाई वाले कुर्ते-पायजामों की कीमत 2,000-2,500 रुपये तक जाती है।

BRIEF NEWS बिजली बिल प्रणाली से लोग परेशान, सरकार से सुधार की मांग

RANCHI: झारखंड राज्य के बिजली उपभोक्ता झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की वर्तमान बिल प्रणाली से परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें बार-बार बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। खासकर उन लोगों को जो एंड्रॉयड मोबाइल या इंटरनेट सेवाओं से वंचित हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। कई उपभोक्ताओं को सही समय पर मासिक बिल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें भारी भरकम बिल मिल रहा है। समय पर बिल न मिलने और उच्च बिल की समस्या के कारण लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर और पोस्टपेड, प्रीपेड सिस्टम के कारण समस्याएं और बढ़ गई हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायतें ई-मेल के माध्यम से भी भेजते हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। सैयद फराज अब्बास, उपभोक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता ने सरकार और विभाग से अनरोध किया है कि बिजली बिल प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।

झामुमो का केंद्रीय महाधिवेशन १४ अप्रैल से, समितियां गटित

RANCHI: झामुमो का 133वां केंद्रीय महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिनके संचालन की जिम्मेदारी केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सौंपी गई है। केंद्रीय महाधिवेशन के लिए तीन प्रमुख समितियों का गठन किया गया है। इनमें राजनीतिक प्रस्ताव सह आगामी कार्यक्रम और रूप-रेखा समिति, संविधान संशोधन समिति और आयोजन सह स्वागत समिति का नाम शामिल है। राजनीतिक प्रस्ताव सह आगामी कार्यक्रम और रूप-रेखा समिति में पार्टी नेता प्रो स्टीफन मरांडी, विनोद कुमार पांडेय, दीपक बिरुआ, महुआ माजी, बसंत सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, सुप्रियो भट्टाचार्य, हेमलाल मुर्मू, मिथिलेश ठाकुर और हफीजल हसन को शामिल किया

रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले में आरोप गठन पर सुनवाई १७ को

RANCHI: रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपित राजीव कमार सिंह और मनीष कमार सिन्हा के खिलाफ आरोप गठन पर सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी। मामले में मंगलवार को सुनवाई की तारीख पूर्व से निर्धारित थी। लेकिन निर्धारित तारीख को आरोप के बिंदु पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 अप्रैल निर्धारित की है। अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज याचिका बीते छह अप्रैल को खारिज कर चुकी है। मामले की सुनवाई साइबर क्राइम एंड ड्रग कॉस्मेटिक मामले के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत में हो रही है।

हॉस्पिटल में कैथलैंब का रास्ता साफ, विभाग ने भी दे दी है मंजूरी

अब सदर अस्पताल में भी होगी दिल की सर्जरी

सदर हॉस्पिटल में मरीज के लिए लगातार सविधाओं में बढोतरी हो रही है। एक के बाद एक नई सुविधाएं मरीजों के लिए शुरू की जा रही हैं। अब दिल के मरीजों के लिए राहत की खबर है। जी हां, 3-4 महीने में सदर में भी दिल के मरीजों की सर्जरी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं उन्हें पेसमेकर लगाने से लेकर एसटेंट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इससे मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में भारी भरकम बिल नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई और सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे मरीजों को सारी सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे मिलने लगेंगी। डाका नहीं पड़ेगा। वहीं सस्ते कैथलैब बनने से तेज होगी सर्जरी दर पर बेहतर इलाज सदर में : फिलहाल हॉस्पिटल में हार्ट के ही मिल सकेगा। जांच की मरीजों को ओपीडी और इनडोर की सुविधा बेहतर होने से मरीजों सुविधाएं मिल रही हैं। अब कैथलैब का सटीक इलाज हो सकेगा। बन जाने से मरीजों को ओपीडी के साथ ही सर्जरी की सविधा भी दी करना होगा। इसके बाद कैथलैब का जाएगी। इसके लिए कैथ लैब बनाने लाभ हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों का काम जल्द शुरू होगा। स्वास्थ्य को मिलने लगेगा। फिलहाल डॉक्टर विभाग से मंजूरी मिलने के बाद मरीजों को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं जिला स्तर पर टेंडर निकालने की और इनडोर में मरीजों को भर्ती कर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं



फिलहाल मरीज गंभीर बीमारियों की स्थिति रिम्स जाना ही बेहतर समझते है। लेकिन, कुछ दिनों में सदर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुड़े हैं। वहीं मरीजों को आन कॉल भी इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में कैथलैब, सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा मिलने से मरीज इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। इससे राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स पर मरीजों का लोड थोड़ा कम होगा।

जगह अब सदर में पहुंचेंगे। चंकि इससे पहले केवल सरकारी हॉस्पिटलों में रिम्स में ही कैथलैब की सुविधा है। इलाज किया जा रहा है। ऐसे में जब

10 दिनों में आ जाएगी सीटी स्कैन मशीन : हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन लगाने को लेकर

चुका है। अप्रैल के पहले हफ्ते में मशीन आ जाएगी। इंस्टालेशन के बाद इसका ट्रायल होगा। वहीं मरीजों का सस्ते दर पर सीटी स्कैन शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में मरीजों को अब सीटी स्कैन कराने के लिए प्राइवेट सेंटरों की दौड़

पहाड़िया बच्चों की मौत पर सरकार गंभीर जांच कर रहा विभाग : इरफान अंसारी

जिले में पहाडिया जनजाति के बच्चों की हो रही रहस्यमयी मौत से स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। पिछले 10 दिनों में पांच बच्चों की हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर इसकी जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस मामले में मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विभाग इसको लेकर गंभीर है और इसकी जांच कराई जा रही है। मामले पर स्थानीय सिविल सर्जन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर भी इसकी जांच हो रही है कि आखिर मौत की वजह क्या है।

चुटिया में 20 अप्रैल से रामकथा का आयोजन

RANCHI: श्री राम कथा का आयोजन 20 अप्रैल से 29 अप्रैल को चुटिया स्थित हाई टेंशन दुर्गा मंदिर में आयोजित किया जाएगा। इसमें लक्ष्मी कुबेर यज्ञ, आयुर्वेद शिविर का भी आयोजन होगा। इस राम कथा में मख्य कथा वाचक श्री श्री 1008 महात्मा मंडलेशवर ब्राह्मयांड स्वामी पुरी महराज होंगे । इस संबंध में मंगलवार को श्री राम कथा के भव्य आयोजन की सफलता को लेकर महात्मा साई संजीवनी सेवा की ओर से हाईटेंशन दुर्गा मंदिर में समीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।



विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री इरफान अंसारी व अन्य

उन्होंने कहा कि पहाड़िया बच्चों की मौत के पीछे क्या इम्यूनिटी की कमी तो नहीं है, इन सभी वजहों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में पूरी

बता दें कि साहिबगंज के मंडरो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नगरभिट्टा पहाड़

पर 10 दिनों में पांच मासूम बच्चों की मौत हो गई है। मौत के कारण को ढुंढने में जुटे स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इसके पीछे ब्रेन मलेरिया हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित बच्चों को सबसे पहले सर्दी, खांसी, तेज बुखार और सर दर्द होता है।

श्रद्धा-भक्ति के साथ मनाया गया पापमोचनी एकादशी का उत्सव

अग्रसेन पथ स्थित श्री श्याम मन्दिर में मंगलवार को पापमोचनी एकादशी उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही भक्त प्रभ के दर्शन के लिए उमड रहे थे। मंदिर में भगवान को नवीन वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलों जैसे गलाब, जही, मोगरा और तुलसी दल से सुंदर श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर शिव परिवार और बजरंगबली का भी विशेष श्रृंगार किया गया। जयकारों के बीच भक्तों ने ज्योत प्रज्वलित की और आहुति देकर मंगलमय जीवन की कामना



संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें भक्त भजनों की धन पर झमते नजर आए। महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। इस आयोजन को सफल बनाने में रमेश सारस्वत, ओम जोशी, चंद्र प्रकाश बागला, धीरज बंका और अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। यह जानकारी मीडिया

मणिपुर और परिसीमन मुद्दे पर दिगभ्रमित नहीं करे झारखंड मुक्ति मोर्चा : प्रतुल शाहदेव

कैथलैब की सुविधा मिलेगी तो

इलाज के लिए मरीज प्राइवेट की

PHOTON NEWS RANCHI: मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मणिपुर और परिसीमन मुद्दों पर दिए गए बयानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि झामुमो जनता को दिगभ्रमित करने का प्रयास कर रही है। प्रतल ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, जिसने हमेशा राष्ट्र और सनातन के हित में काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो संघ के बयानों को गलत तरीके से पेश कर

टेंडर के बाद 90 दिनों में चुनी जाने

वाली एजेंसी को कैथलैब तैयार



हताशा का परिणाम है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस झामुमो के कार्यकाल में झारखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदनामी हुई, वही अब एक राष्ट्रवादी संगठन पर टिप्पणी कर रहा है यह शोभनीय नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि संघ ने कभी परिसीमन का विरोध नहीं किया और इसका स्पष्ट मत है कि परिसीमन को इस तरह लागू किया जाना चाहिए। जिससे देश की एकता और अखंडता मजबत हो सके।

होगा विवाद का समाधान : प्रतल ने यह भी कहा कि मणिपुर पर संघ का बयान झाममो ने गलत तरीके से प्रस्तत किया है। संघ का मानना है कि मणिपुर पिछले 20 महीनों से कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रशासनिक फैसलों से स्थिति में सधार हो रहा है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल ने राज्य में सरकारी टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा-चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की उड़ाई जा रहीं धज्जियां

PHOTON NEWS RANCHI: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबुलाल मरांडी ने मंगलवार को झारखंड की सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी टेंडर आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर लगातार संदेह बना हुआ है और यह हालात जनता के लिए चिंता का कारण हैं। उन्होंने कहा कि महालेखाकार की हालिया रिपोर्ट में यह खलासा हुआ है कि कई विभागों, जैसे पेयजल स्वच्छता,

ग्रामीण कार्य विकास, गृह कारा

और आपदा प्रबंधन में एक ही



राज्य के विकास में बन रही बाधक

बाबुलाल मरांडी ने कहा कि यह स्थिति न केवल राज्य के विकास में बाधक बन रहीं है, बल्कि झारखंड की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि अगर जल्द ही कड़े कदम नहीं उढाए गए तो आम जनता का सरकारी तंत्र पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि टेंडर प्रक्रिया में जवाबदेही तय की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता के पैसों की लूट रोकी जा सके।

आईपी एडेस से टेंडर भरे गए थे। यह स्पष्ट करता है कि ठेके पहले से तय थे और प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन विभागों में चहेते लोगों को

लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुणवत्ता पर भी पड़ेगा असर : नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि यदि टेंडर आवंटन में इस तरह की अनियमितताएं होती रहेंगी तो

इसका असर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी पडेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जलमीनार ध्वस्त हो रहे हैं, सड़कों का काम महीनों में ही जर्जर हो जाता है।

झारखंड के मौसम का बढने लगा तापमान, पडेगी प्रचंड गर्मी

PHOTON NEWS RANCHI झारखंड के अधिकांश जिलों में पिछले दिनों बारिश से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। लेकिन गर्मी एक बार से राज्य के लोगों को रुलाने को तैयार है।

रही है, जो कि उसकी खीज और

आनेवाले दिनों में झारखंड में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इससे तापमान में तेजी से वद्धि होने की संभावना है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया कि अगले चार-पांच दिनों में राज्य के विभिन जिलों में तापमान में चार से पांच डिग्री की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि मौसम में अभी फिलहाल कोई



सिस्टम बनता है नहीं दिख रहा है। इसलिये आनेवाले दिनो में प्रचंड गर्मी पड़ सकती है।

वहीं मंगलवार को रांची और आसपास के इलाकों में दिनभर माउस साफ रहा। सुबह में हल्की ठंड रही, लेकिन दोपहर में लोगों को गर्मी का अनुभव हुआ।



विकास पदाधिकारी को आवश्यक इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्देश देते हुए कहा कि लाभकों आनेवाले समय में सार्थक प्रयास किये जायेंगे। जिला दंडाधिकारी-के लिए मुर्गी पालन, अंडा एवं सह-उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने डेयरी उत्पादन कैसे लाभकारी हो मंगलवार को ऑनलाइन बैठक सकते हैं इसके लिए कार्ययोजना करते हुए योजना अंतर्गत वर्ष में प्रत्येक लाभुकों को मिलनेवाली

पोल्ट्री फार्मिंग से पोषण, स्वावलंबन एवं समृद्धि : उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत जो राशि लाभुक मंईयां के खाते में जा रही है उसका

सदपयोग करके महिलाएं सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही राशि को कई गना कर सकती हैं। इस कार्य में जिला प्रशासन द्वारा किस प्रकार से सहयोग दिया जा सकता है इसकी विवेचना की जाए। उपायक्त ने कहा कि इस दिशा में पोल्टी फार्मिंग से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पोल्टी फार्मिंग से महिला स्वावलंबन की दिशा में बहुआयामी लाभ प्रत्येक परिवार को प्राप्त होंगे। इससे किशोरियों के पोषण, महिलाओं के स्वावलंबन एवं अर्थव्यवस्था को मिलेगी।डीपीएम जेएसएलपीएस को उन्होंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ रविवार को बैठक करने के

भी निर्देश दिए।

शांति समिति की बैठक में त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील



मंगलवार को बेड़ो थाना परिसर में मंगलवार को ईद, सरहुल और रामनवमी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी अशोक कुमार ने की। ईदगाह की नमाज की जगह, सरहुल जुलूस और रामनवमी जुलूस मार्ग की जानकारी ली। बीडीओ राहुल उरांव, सीओ प्रताप मिंज ने कहा

कि सभी समुदायों को आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ अपने-अपने त्योहार मनने को कहा। किसी भी तरह के सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने और सभी लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान ने कहा कि शांति भंग करने की या किसी भी तरह की गड़बड़ी या नुकसान की शिकायत मिले तुरंत सूचना दें।

संभावित जल संकट को दूर करने के लिए अधिकारियों ने की मीटिंग

राजधानी के लिए नगर निगम ने तैयार किया समर एक्शन प्लान

गर्मी में जल संकट से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को प्रशासक कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। अध्यक्षता रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने की। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन क्षेत्रों और मुहल्लों को चिह्नित किया जाए, जो ड्राई जोन के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए मोबाइल टैंकरों के माध्यम से निःशुल्क जलापूर्ति का रोस्टर तैयार किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निगम क्षेत्र के भीतर स्थापित चापाकल, एचवाईडीटी और मिनी

हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत जलापूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए निगम ने हेल्पलाइन नंबर 18005701235

11111 HH III II

और 9431104429 जारी किया है। इन नंबरों पर लोग संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए डोर-ट्-डोर विजिट करने का निर्देश

30 हजार सम्मान राशि के

सदुपयोग से महिलाओं को

स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य

योजना बनाने के निर्देश दिए।

पदाधिकारी एवं जिला गव्य

पशुपालन

जिला

RANCHI : रांची नगर निगम ने राजस्व विभाग की टीम को टास्क दिया है। इसके तहत टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए डोर-टू-डोर विजिट कर जांच करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, टैक्स देने में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। बता दें कि उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने समीक्षा के बाद वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैक्स कलेक्शन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं।

टैक्स वसूली पर जोर: उप प्रशासक ने राजस्व शाखा की टीम को कड़ी मेहनत करने और समर्पण के साथ लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और एजेंसी के टैक्स कलेक्टर को सभी वार्डों में डोर-टू-डोर विजिट करने का निर्देश दिया, ताकि व्यापक स्तर पर टैक्स की वसूली की जा सके। बड़े बकाएदारों पर भी नजर: टीम को बड़े बकाएदारों से संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि निगम द्वारा पूर्व में बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी किया गया था। उन बकाएदारों से पुन: संपर्क कर कर वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही टैक्स का भुगतान करने में रुचि नहीं दिखाने वाले हाउस होल्डर को चिन्हित करने और उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

एचवाईडीटी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को 24 घंटे के उप प्रशासक गौतम कुमार, अधीक्षण अभियंता प्रसुन कुमार कार्यपालक अभियंता राम

बदन सिंह, सहायक अभियंता और नगर प्रबंधक भी उपस्थित थे। निगम प्रशासक ने सभी नागरिकों से

अपील की कि वे अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाएं और वर्षा जल का संचयन करें।

शिक्षा मंत्री के जुर्माना संबंधी बयान पर पेरेंट्स एसोसिएशन ने उटाए सवाल

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने स्कूलों पर ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही थी। अजय राय ने इसे महज एक बयान करार देते हुए कहा कि आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जहां इस तरह की कार्रवाई किसी स्कूल के खिलाफ की गई हो। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंत्री जी इस बात का कोई रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई किसी स्कूल पर हुई हो, जबिक अभिभावकों ने लगातार इसका विरोध किया है।

स्कूलों का बढ़ा मनोबल: अजय राय ने कहा कि यह बयान केवल



आई वाश है, जिसके कारण स्कूलों का मनोबल इतना बढ़ चुका है। वे अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाने, किताबों में कमीशन वसूलने और री-एडमिशन के नाम पर छात्रों से पैसे मांगने का काम करते हैं। उन्होंने झारखंड विधानसभा में झरिया की विधायक रागिनी सिंह द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उठाए गए सवालों का हवाला दिया। रागिनी सिंह ने बताया था कि प्राइवेट स्कुल हर साल 10 से 20 प्रतिशत तक फीस बढ़ा देते हैं, इसके अलावा किताबों की बिक्री में भी कमीशन वसूला जाता है और छात्रों को खास किताबों के लिए मजबूर किया जाता है।

स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए सरकार : उन्होंने यह भी बताया कि पिछले लगभग 10 सालों के संघर्ष के बाद झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 का गठन हुआ था, लेकिन इसका सही तरीके से क्रियान्वयन कहीं भी नहीं हो रहा है। इसके बावजूद स्कूल अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं और इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जो राज्य के लिए दुखद है।

समाचार सार

एन सिंघानिया जिला अंडर-16 क्रिकेट कल से

CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की ओर से नथमल

क्रिकेट प्रतियोगिता 27 मार्च से चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में प्रारंभ होने जा रहा है। संघ के के उपाध्यक्ष सुशील कुमार

सिंघानिया द्वारा प्रायोजित ओपेन लीग आधार पर होने वाली प्रतियोगिता में कुल छह लीग मैच खेले जाएंगे।

किरीबुरू में गर्ल्स कबड्डी आज से

CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सेल किरीबुरू आयरन ओर माइंस की ओर से फुटबॉल ग्राउंड, किरीबुरू में 26 मार्च से दो दिवसीय गर्ल्स कबड्डी टूनामेंट होगा। प्रतियोगिता में कुल छह टीमें भाग लेंगी, जिनमें किरीबुरू और आसपास के स्कूलों की छात्राएं शामिल होंगी।

देश के विकास के लिए रिसर्च जरूरी : प्रो. कवात्रा



रहे तृतीय प्लेटिनम जुबिली समारोह के अंतर्गत मंगलवार को व्याख्यान हुआ। इसमें यूनिवर्सिटी, हॉटन, मिशिगन, यूएसए के प्रो. एसके. कवात्रा

सबसे पहले लौह अयस्क प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनाए गए विभिन्न नवाचारों और पहलों पर प्रकाश डाला। उनके जीवंत प्रस्तुतिकरण को दर्शकों ने खूब सराहा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए रिसर्च बेहद जरूरी है। नए रिसर्च से देश के विकास की गति तेज होती है। इससे पहले सीएसआईआर-एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने श्रोताओं का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सीएसआईआर-एनएमएल के वैज्ञानिक, तकनीकी कर्मचारी, छात्र, शोधकर्ता और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। मुख्य वैज्ञानिक डॉ. वीसी. श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

तेतुलडांगा की बिजली समस्या हुई दूर

GHATSILA: मौदसोली पंचायत के तेतुलडागा कॉलोनी में बिजली की समस्या दूर हो गई। 5 दिन से



अंधेरे में रही कॉलोनी मंगलवार को तब जगमगा उठी, जह 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगा। इसके लिए अधिकारी ने जुनबनी पंचायत के उप मुखिया सुजन कुमार

मान्ना को दी थी। इस मौके पर दीपू अधिकारी, निर्मल मिस्त्री, बप्पा मिस्त्री, श्यामल सरकार आदि उपस्थित थे।

फूड लाइसेंस के लिए 88 ने किया आवेदन

CHAKRADHARPUR : उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर



फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन का शिविर लगा, जिसमें 88 आवेदन आए।

पदाधिकारी अभिषेक आनंद भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि सभी खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

आज से 28 तक पटमदा रूट रहेगा डायवर्ट

JAMSHEDPUR: टाटा स्टील युआईएसएल द्वारा डिमना घाटी रोड पर री-सर्फेसिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण, पटमदा से आने वाले वाहनों के लिए पटमदा मोड से काली मंदिर की ओर तथा पटमदा जाने वाले वाहनों के लिए डिमना चौक से काली मंदिर की ओर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। यह डायवर्सन 26 से 28 मार्च तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। डिमना चौक से नए एमजीएम तक

ब्रह्मर्षि समाज का सामूहिक उपनयन 13 से

JAMSHEDPUR: ब्रह्मर्षि विकास मंच जमशेदपुर के तत्वाधान में 13 अप्रैल से सामहिक उपनयन संस्कार प्रारंभ होगा। संस्था का यह जमशेदपुर में लगातार सातवां वर्ष है। इस वर्ष यह आयोजन अमल संघ मैदान, सिदगोड़ा में होगा।

वाईआई, जमशेदपुर को मिले ८ पुरस्कार



स्थित होटल अलकोर में आयोजित वाईआई ईस्टर्न रीजन काउंसिल मीटिंग (ईआरसीएम) का समापन मंगलवार को हुआ। इसमें पूर्वी भारत के 9 चैप्टर और

120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वाईआई जमशेदपुर को 6 क्षेत्रीय और 2 चैप्टर पुरस्कार मिले। मीटिंग के दौरान नेतृत्व, नवाचार और सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। रोमांचक गतिविधियों में टाटा मोटर्स का औद्योगिक भ्रमण, जमशेदपुर ट्रेजर हंट और एक्सएलआरआई के प्रो. सुनील कुमार षाड़ंगी द्वारा प्रेरणादायक सत्र शामिल था।

गुड़ाबांदा में हाथी ने युवक को खेत में पटक कर मार डाला

मंत्री रामदास सोरेन ने लिया संज्ञान, मिलेगा मुआवजा अनियंत्रित ट्रक बस स्टैंड में

गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट पंचायत पंडारशोली गांव निवासी 44 वर्षीय हाड़ीराम मुर्मू को हाथी ने पटक कर मार डाला। घटना मंगलवार की सुबह 9 बजे की है। परिवार वाले हाडीराम मुर्मू को तत्काल अनुमंडल अस्पताल घाटशिला लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी चूड़ामणि मुर्मू ने बताया कि पति सुबह घर से 9 बजे शौच के लिए जंगल गया था। काफी देर बाद जब घर नहीं लौटा तो जंगल की ओर खोजने गई। जंगल में पति अचेत पड़ा हुआ था। गांव वालों की मदद से उसे उठाकर अनुमंडल अस्पताल

लाया गया। सूचना मिलते ही

बारीडीह में निकली निशान यात्रा में लोग व कलाकार

(पोस्टऑफिस) मैदान

मंगलवार को श्याम महोत्सव

हुआ, जिसमें श्याम भक्त सुबह से

देर रात तक झुमते रहे। श्री श्याम

दीवाने परिवार की ओर से

महोत्सव में दोपहर 3 बजे बजरंग



अस्पताल पहुंचे परिजन व अन्य

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपने प्रतिनिधि जगदीश भकत को अनुमंडल अस्पताल जाने

भकत ने बताया कि मुसाबनी के रेंजर को घटना की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई को कहा

श्याम महोत्सव में झूम उठा

बारीडीह, झांकी ने मोहा मन

चौक बारीडीह बस्ती से निशान

यात्रा निकाली गई, जिसमें बंगाल

के कलाकारों ने एक से बढ़कर

एक झांकी प्रस्तुत की। वहीं,

भजन संध्या में कोलकाता से आए

सौरभ कुमार और वृंदावन से आए

गायकों के साथ शहर के गायकों

ने भी बाबा श्याम के दरबार में

भजनों की अमृतवर्षा से श्रोताओं

का निर्देश दिया।

गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग से जो भी सरकारी मआवजा होगा, वह तत्काल दिया जाएगा। इसके साथ ही मृतक की पुत्री का नामांकन कस्तरबा विद्यालय में करने की





घुसा, बाल-बाल बच गए लोग

के फलडंगरी चौक के समीप मंगलवार को एक अनियंत्रित ट्रक हाईवे के सर्विस रोड से बस स्टैंड में घुस गई। हालांकि इस दुर्घटना में जान–माल का नुकसान नहीं हुआ, पर घाटशिला जाने वाली मुख्य सड़क पर परी तरह जाम लग गया। समाचार लिखे जाने तक ट्रक सड़क पर ही खड़ी थी। घटना के संबंध में पत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोपहर

रोड से ट्रक घाटशिला जाने वाली मुख्य सड़क की ओर मुड़ गई। बस रटैंड पर खड़े यात्रियों में अफरातफरी मच गई। चालक वाहन को नियंत्रित न करता, तो बड़ी दर्घटना हो सकती थी। वहां काफी संख्या में स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं सहित अन्य यात्री बस के इंतजार में खड़े थे। चालक ने बताया कि क्लच प्लेट जल जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी। मौके का फायदा उताकर



अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दो की मौत



GHATSILA: धालभमगढ थाना क्षेत्र के कोकपाड़ा में मंगलवार को देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दो युवकों की मौत हो गई। घटना हनुमान मंदिर के समीप हुई, जब दोनों यवक एनएच-18 पार कर रहे थे। दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। एक युवक की पहचान कोकपाड़ा निवासी तपन देहुरी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वह किसी वाहन का चालक बताया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद धालभूमगढ़ के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृतक के हटाया। जानकारी के अनुसार, बताया जाता है कि मृतक तपन देहुरी कोलकाता में किसी कंपनी में काम करता था। डेढ़ माह पहले ही अपने घर आया था। कोकपाड़ा के बाबूपाड़ा निवासी स्व. नरेश देहुरी का 26 वर्षीय पुत्र तपन देहुरी किसी काम से कोकपाड़ा हनुमान मंदिर के समीप आया था। इसी दौरान किसी जान हचान के चालक के साथ वह सड़क पार कर एक दुकान से गुटखा लाने जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन

मंगला पूजा कर महिलाओं



तथा बच्चे शामिल थे।

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना क्षेत्र के भरभरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के भरभरिया थाना क्षेत्र में नाबालिंग के साथ कांडे बिरुवा व गुरुचरण पिंगुवा ने 13 अप्रैल 2023 को दुष्कर्म करने के आरोप में पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में उसने बताया था कि मंझारी थाना क्षेत्र के भरभरिया निवासी कांडे बिरुवा व गुरुचरण पिंगुवा ने सुनसान जगह पर उसे ले जाकर जबरदस्ती बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इसके बाद



ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

कांडे बिरुवा व गुरुचरण पिंगुवा उसे इस बात की जानकारी किसी को न देने की बात कही थी, नहीं तो जान से मार देने की धमकी दी थी। घटना के बाद पीड़िता द्वारा थाना में की गई लिखित शिकायत के बाद अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा

अभियुक्त कांडे बिरूवा एवं गुरुचरण पिंगुवा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र

ईपीएस से न्यूनतम पेंशन ७,५०० रुपये करने की मांग पर प्रदर्शन

JAMSHEDPUR : ईपीएस- 95 राष्टीय संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को भविष्य निधि (पीएफ) कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के प्रतिनिधिमंडल ने चार सूत्री मांगों को लेकर पीएफ कमिश्नर से मुलाकात की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी न्यायोचित मांगों को लेकर वे पिछले नौ वर्षों से संघर्ष कर रहे लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। संघर्ष समिति के सचिव कालीपद सई ने बताया कि देशभर के 27 राज्यों में कार्यरत पेंशनर पेंशन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 78 लाख पेंशनर आर्थिक बदहाली का सामना कर

रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी

समस्याओं की अनदेखी कर रही

यह हैं प्रमख मांगें

- नतम पशन ७५०० रुपए प्रति माह की जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता दिया जाए। • पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा
- सुविधा उपलब्ध कराई जाए। • सुप्रीम कोर्ट के ४ नवंबर 2022 के आदेश के अनुसार सभी पेंशनरों को समान रूप
- ईपीएस 95 के वंचित पेंशनरों को ५००० रुपये मासिक पेंशन दी जाए।

से उच्च पेंशन का लाभ दिया

है। पेंशनरों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे सडकों पर उतरने के लिए

सीतारामडेरा से एक अप्रैल को निकलेगी सरहुल शोभायात्रा

को बांधे रखा। गणेश मित्तल,

मुकुंद पांडे व रवि पांडे की ओर

से हुए कार्यक्रम में बाबा की

अखंड ज्योत और फूलों के

श्रंगार ने हर किसी को मुग्ध कर

दिया। शीश के दानी बर्बरीक की

महाभारत काल से ही पूजा की

जाती है, जिन्हें खाटू श्याम के

नाम से जाना जाता है।



JAMSHEDPUR: केंद्रीय सरहुल पूजा समिति, पूर्वी सिंहभूम ने मंगलवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि शहर में सीतारामंडेरा से सरहुल की शोभायात्रा 30 मार्च को नहीं, एक अप्रैल को निकलेगी। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी एवं मूलवासी एकता को भंग करने के उद्देश्य से मुंडा समाज, सोपोडेरा के नाम से राम सिंह मुंडा द्वारा लोगों को दिगभ्रमित करके 30 मार्च को सरहुल शोभायात्रा निकाली जा रही है, जिसका हम सभी आदिवासी एवं मूलवासी समुदाय के लोग विरोध करते हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में सरहुल पर्व 1 अप्रैल को मनाया जा रहा है। प्रतिनिधमंडल में किशोर लकड़ा, नंदलाल पातर, राजश्री नाग, राकेश उरांव, राजेश कांडयोंग, शंभू मुखी डुंगरी, प्रेम आनंद सामद, निकिता सोय बुरुली आदि शामिल थे।

नए रेल ट्रैक पर ७५ किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से किया गया ट्रायल



CHAKRADHARPUR:

किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निरीक्षण मोटर ट्रॉली में बैठ कर किया। इस दौरान पीसीसीओ ने डुमरता स्टेशन में किए गए एनआइ वर्क, सिग्नल, आदि का निरीक्षण कर रेल लाइन की गुणवत्ता की



निरीक्षण के दौरान उपस्थित रेलकर्मी

• फोटोन न्यूज

जांच परख की। उनके साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के तमाम रेल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। यह स्पीड टेस्ट 13.25 बजे से 13.40 बजे तक चला। ज्ञात हो कि पीसीएसओ द्वारा किए गए इस स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट कमिश्नर

ऑफ रेलवे सेफ्टी अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अधिकारी पुनः स्पीड टेस्ट करेंगे। उनकी अनमति मिलने के बाद ही इस नवनिर्मित रेल लाइन पर यात्री और मालगाडी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।

आईएसबीटी के लिए अस्थायी शेड निर्माण, शौचालय आदि को लेकर दिया गया निर्देश

फरवरी में हुईं 33 सड़क दुर्घटनाएं, 25 की हो गई मौत, 20 गंभीर रूप से घायल

समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में यातायात व सड़क सुरक्षा पर बैठक हुई। इसमें सड़क हादसों को नियंत्रित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने समेत अन्य संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि फरवरी में 33 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु व 20 लोग गंभीर रुप से घायल हुए। वल्नरेबल एक्सीडेंटल प्वाइंट्स एवं सड़कों के कर्व (घुमाव) स्थलों को चिह्नित करते हुए आवश्यकतानुसार सुधार करने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, बिना सीट बेल्ट व यातायात नियमों के अन्य प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया।



सड़क सुरक्षा की बैठक को संबोधित करते उपायुक्त अनन्य मित्तल

शहर के कुछ स्थान खतरनाक इसके साथ ही शहर के कुछ स्थान खतरनाक बन गए हैं, जिसमें जेम्को, दोमुहानी, एमजीएम आदि में अक्सर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम को लेकर विशेष पहल करने का निर्देश दिया गया। उप नगर आयुक्त जेएनएसी, ट्रैफिक डीएसपी व टाटा स्टील के प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण कर जेम्को क्षेत्र में भारी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिह्नित करने का निर्देश दिया गया, जिससे वाहनों की पार्किंग सड़क पर नहीं हो।

फरवरी में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 572 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया

गया। वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया

पर्वी सिंहभुम में चिह्नित किए गए ९ ब्लैकस्पॉट सड़के दुर्घटनाओं की समीक्षा में नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे अवैध रूप से

पार्किंग करना, गलत साइड में ड्राइविंग व ओवरस्पीड प्रमुख कारण पाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे में 9 स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने हाईवे पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध ठोस कार्रवाई को लेकर हार्ड बैरिकेडिंग किए जाने, हाईवे में मिलने वाली कनेविटंग रोड के पास ब्लिंकर्स लगाने व ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए चिह्नित स्थलों पर बैरियर लगाने के सुझाव दिए। उपायुक्त ने एनएचएआई के पदाधिकारी को उक्त सुझावों पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। हाईवे में सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय जरूर किए जाएं, जिससे जानमाल का नुकसान नहीं हो।

ऑटो चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के दौरान जिला के वरीय पदाधिकारियों ने साकची गोलचक्कर पर ऑटो चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक निर्धारित पार्किंग स्थल में ही ऑटो लगाएं और सवारी बैटाएं। अंडरएज व बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चालकों की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। यातायात नियमों की अवहेलना पर जुमार्ना वसूलने का निर्देश दिया गया।

वाहन चालकों समेत यातायात वसुला गया। 1928 नए ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन के अन्य मामलों लाइसेंस बनाए गए, जिनमें 1637 में 14 लाख 50 हजार रुपये जुमार्ना पुरुष व 291 महिलाएं हैं।

मानगो बस स्टैंड से जर्जर बर्सो को हटाएं

बैठक में मानगो बस स्टैंड में वर्षों से पड़े जर्जर बसों को हटाए जाने तथा अंतरराज्यीय बसों के लिए आईएसबीटी को अस्थायी तौर पर विकसित करते हुए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम व मानगो नगर निगम के पदाधिकारी को आईएसबीटी में यात्रियों की सुर्विधा के लिए अस्थायी शेड निर्माण व चलत शौचालय को लेकर पहल करने का निर्देश दिया गया।

स्कुली बच्चों को जागरूक करें यंग इंडियंस

उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक ने भारी वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश यंग इंडियंस के प्रतिनिधियों को दिया। यंग इंडियस द्वारा निजी स्कूलों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की भी समीक्षा की गई तथा इसे और प्रभावी, रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने का निर्देश दिया गया, ताकि स्कूली बच्चे व चालकों को आसान भाषा में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके।

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में एडीएम अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, डीटीओ धनंजय, उप नगर आयुक्त जेएनएसी कृष्ण कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण दीपक सहाय, डीएसपी भोला प्रसाद, डीएसपी ट्रैफिक, एमवीआई सूरज हेंब्रम, यंग इंडियस, ट्राटा स्टील व् जुस्को, बस एसोसिएशन एवं ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

जदयु के जिला महामंत्री बने पन्नु व हरेराम सिंह

JAMSHEDPUR: जदयू, पूर्वी

सिंहभूम जिला कमेटी का विस्तार किया गया है। इसमें कुलविंदर सिंह पन्नूव हरेराम सिंह महामंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा कमेटी में उपाध्यक्ष एम चंद्रशेखर राव, अशोक कुमार सिंह, मनोरंजन महतो, भास्कर मुखी, दुर्गा राव, परमजीत श्रीवास्तव, गणेश नायर व दिनेश्वर कुमार, मंत्री अमित कुमार सिंह, कन्हैया ओझा, मृत्युंजय कुमार सिंह, प्रेम सक्सेना, जितेंद्र सिंह, असीम पाठक, बिनोद सिंह, राजेश कुमार, जितेंद्र कुमार, भरत पांडे, विकास साहनी व चंदा मुखी, कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, संगठन समन्वय विजय सिंह, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश कोया, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष राजेश मुखी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अजीत कुमार व युवा मोर्चा अध्यक्ष नीरज सिंह बनाए गए हैं।

बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी, 86.50 फीसद परीक्षार्थी सफल

बेटियां रहीं तीनों संकायों मे<u>ं टॉप</u>र

AGENCY PATNA : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट (12वीं) का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी किया है। मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। इंटर की परीक्षा में कुल 86.50 फीसदी परीक्षार्थी सफल हुए हैं। पश्चिम चंपारण की बेतिया स्थित राज्य संपोषित एसएस प्लस टू स्कूल हरनाटांड की छात्रा प्रिया जायसवाल साइंस टॉपर बनीं हैं। कॉमर्स में टॉपर वैशाली की रौशन कुमारी है, जिन्होंने 500 में से



रिजल्ट जारी करते शिक्षा मंत्री सुनील कुमार व अन्य

सुधीर कुमार की बेटी हैं। आर्टस 94.6 फीसदी यानी 473 अंक

475 अंक हासिल किया है।रौशनी में हाजीपुर की छात्रा अंकिता कुमारी वैशाली के रहने वाले कुमारी टॉपर बनीं हैं। अंकिता ने

हासिल कर आर्ट्स टॉपर बनी हैं। अंकिता राजकीयकृत वीएन उच्च

अनिल कमार शर्मा की बेटी हैं। इस तरह इस साल इंटमीडिएट की तीनों संकाय की परीक्षा में तीनों टॉपर बेटियां ही है।

पश्चिम चंपारण की साइंस टॉपर प्रिया जायसवाल को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने टॉप किया है। प्रिया ने कहा मैं मार्केट में थी, तभी फोन आया कि मैंने टॉप किया है। पहले तो मुझे लगा कि बिहार में कई प्रिया होंगी लेकिन जब पूरा नाम बताया तो यकीन हुआ।

मैंने मेहनत तो की थी लेकिन टॉप करने की उम्मीद नहीं थी। मेरी दीदी मुझे रातभर पढ़ाती थीं। मैंने पढ़ाई के साथ-साथ लिखने पर

ज्यादा याद रहीं। मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हुं। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी हर कदम पर मेरा

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी, 2025 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा में लगभग 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, 6,50,466 छात्र और 6,41,847 छात्राएं शामिल हुए थे। यह परीक्षा 38 जिलों में 1,677 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 11,07,213 छात्र-छात्रा सफल

मोतीहारी पुलिस ने चोरी व गुम हुए १२० मोबाइल फोन वास्तविक धारकों को लौटाया

AGENCY CHAMPARAN : जिला पलिस की टीम ने ऑपरेशन मस्कान के तहत एक बार फिर 120 लोगों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल वापस लौटा कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दिया है। बरामद इन मोबाइल की कुल

बैंककर्मी, 6 बिजली मिस्त्री, 1 कीमत लगभग 19 लाख रुपए क्लर्क, 1 जीविका दीदी और 90 बताया गया है। साइबर डीएसपी अन्य लोग शामिल हैं।

उन्होने बताया कि पर्वी चंपारण जिला में ऑपरेशन मुस्कान के 14 चरणों में अब तक कल 1353 मोबाइल बरामद किए गये।जिनकी कल कीमत 2 करोड 80 लाख 51 हजार रुपये है। पलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक धारको को सौंप दिए हैं। डीएसपी अभिनव पराशर ने कहा कि यह अभियान

O BRIEF NEWS मीटिंग में भाग लेने के लिए पेंशनर समाज के प्रतिनिधि गए पटना

ARARIA: पटना के गर्दनीबाग में पेंशनर समाज के राज्य स्तरीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए फारबिसगंज पेंशनर समाज के दो सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ट्रेन से पटना के लिए रवाना हुए। बिहार राज्य पेंशनर समाज का राज्य अधिवेशन कल बुधवार को पटना में आयोजित है। राज्य अधिवेशन में भाग लेने के लिए सदस्य हरिशंकर झा एवं विश्वनाथ पासवान दानापुर जाने वाली इंटर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुए।फारबिसगंज पेंशनर समाज के सचिव मधुसूदन मंडल,उप सचिव विद्यानंद पासवान एवं प्रोफेसर दिलीप कुमार अग्रवाल ने माला पहनाकर प्रतिनिधि सदस्यों को रवाना किया।

सफाई कर्मियों को दिए गए उपकरण

BIHAR SHARIF: बिहारशरीफ नगर निगम कार्यालय में आज मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को आवश्यक उपकरणों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर अनीता देवी. उप महापौर आईशा शाहीन एवं सभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपकरणों में मुख्यतः बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी सफाई कर्मियों, चालकों और वार्ड जमादारों को फुल शर्ट और फल पेंट वाले रेनकोव दिए गए। सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए गलब्स का भी वितरण किया गया। प्रत्येक वार्ड में 4-4 सफाई कर्मियों तथा विशेष नाला गैंग कर्मियों को गमबट दिए गए। नगर निगम के इस प्रयास की सराहना करते हुए महापौर

अनीता देवी ने कहा कि सफाई

कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य

महापौर आईशा शाहीन ने भी

इस पहल को सराहा और कहा

कि इस तरह के उपकरणों का

वितरण कर्मियों के कामकाज

बनाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित

सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों

ने भी नगर निगम के इस कदम

की प्रशंसा की और इसे सफाई

कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण

कदम बताया।

को सुरक्षित और प्रभावी

हमारी प्राथमिकता है। उप

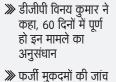
बिहार देश का पहला राज्य, जहां सभी 40 पुलिस जिलों में स्थापित है अजा-अजजा थाना

अनुसूचित जाति-जनजाति मुकदमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीजीपी

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने राज्य के सभी जिलों के पलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की जांच में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों के अनुसूचित जाति-जनजाति थानों के साथ ही सामान्य थानों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान 60 दिनों में पूर्ण किया जाए। डीजीपी ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-संवेदीकरण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रशिक्षण-सह-संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन सीआईडी (कमजोर वर्ग) और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति-जनजाति

कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से

किया। डीजीपी ने ये भी निर्देश दिया



- में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश
- >>> अभियुक्तों को सजा दिलाने की रफ्तार कम
- >> फर्जी मामलों की जांच कर तत्काल करें निपटारा

है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को लटकाए रखने वाले जांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की गति में

तेजी लायी जाए। बिहार में हर साल अत्याचार अधिनियम के तहत औसतन 6 से 7 हजार केस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इन मामलों के अभियुक्तों को सजा दिलाने की रफ्तार कम है। पिछले साल यानी वर्ष 2023-24 में दर्ज मामलों में सजा दिलाने का औसत 10 प्रतिशत से भी कम रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां सभी 40 पलिस जिलों में अनसचित

जबिक देश के विभिन्न राज्यों के महज 140 जिलों में ही अनुसूचित जाति-जनजाति थाने कार्यरत हैं। बिहार के सभी एससी/एसटी थानों में एससी/एसटी वर्ग से आने वाले अधिकारियों की ही तैनाती की गई है। उन्होंने इन थानों के थानाध्यक्षों और एसडीपीओ को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सजा दिलाने की रफ्तार में तेजी लाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अनुसूचित जाति-जनजाति थानों के कार्यरत रहने के कारण यहां अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या भी देश के अन्य राज्यों से अधिक है। डीजीपी ने यह भी स्वीकार किया कि बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति थानों की संख्या अधिक होने के कारण यहां दर्ज होने वाले मामलों की संख्या भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में

हाथ में तख्ती व हरी टीशर्ट पहनकर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन

अभिनव पराशर मंगलवार को

वास्तविक धारको को मोबाइल देते

हुए बताया कि एसपी स्वर्ण प्रभात

के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने

तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के

आधार पर इन मोबाइल फोन को

बरामद किया है। जिन लोगो को

मोबाइल वापस किया गया है,उनमे

12 विद्यार्थी, 2 गृहिणी, 3 किसान,

1 शिक्षक, 2 पुलिसकर्मी, 2

की मंगलवार को शरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक का प्रदर्शन करने का तरीका अलग रहा।

आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद और लेफ्ट के विधायक हरा टीशर्ट पहनकर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे।विपक्ष बिहार में 65 फीसदी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार मांग उठा रहा है।

राजद विधायकों का कहना था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था लेकिन उसे नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार 65 फीसदी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल करे। इसके साथ ही साथ अन्य मांगों को लेकर भी विपक्ष ने अपनी बात सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है। आज दोनों सदनों में आरक्षण के मद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है।



राजद सदस्यों का विधानमंडल में हरे रंग की टी-शर्ट पहन कर आना बिहार की जनता को है सब्जबाग दिखाना : विजय चौधरी

PATNA: संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज बताया कि मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में राजद सदस्यों द्वारा हरे रंग की टी-शर्ट पहनकर सदन में आना उनके द्वारा बिहार की जनता को सब्ज-बाग दिखाने जैसा है। मंत्री चौधरी ने कहा कि टी-शर्ट पर उनके द्वारा तेजस्वी सरकार का जिक्र मिथ्या तथ्य एवं दंभ की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि अहंकार में ये लोग भूल गए कि बिहार में जाति आधारित गणना कराने का फैसला नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन .डी .ए . की हुकूमत में ही लिया गया था। फिर जब गणना के आंकड़े आए तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिनियम भी एन .डी .ए .

की हुकूमत में ही हुआ। ये तो बीच में कुछ दिनों के लिए सरकार में आए थे। मंत्री चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण सीमा बढ़ाने संबंधी कानून बनने के तत्काल बाद इसे नवीं अनुसूची में डालने के प्रयास शुरू कर दिए थे, परंतु इसी बीच पटना उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया। सरकार ने तत्काल उच्चतम न्यायालय में इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर किया और आशान्वित है कि फैसला पक्ष में आएगा। उन्होंने कहा कि आज जब संबंधित कानून ही निरस्त है तो उसे नवीं अनुसूची में डालने की बात करना सिर्फ थोथी दलील है, जिसे जनता समझ रही है।

मुफ्त आइसक्रीम नहीं देने पर जदयू का नारी शक्ति रथ पहुंचा भागलपुर, महिला विक्रेता की गोली मारकर हत्या संवाद यात्रा कार्यक्रम का किया गया आयोजन

जिले के लोदीपुर थाना के कुछ ही दरी पर आइसक्रीम विक्रेता की हत्या को लेकर मंगलवार की सुबह आक्रोशित लोगों ने भागलपुर गोराडीह सड़क मार्ग को जाम कर दिया। उल्लेखनीय है कि बीते देर रात्रि लोदीपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहे सत्संग स्थल के समीप मुफ्त में आइसक्रीम नहीं देने पर आइसक्रीम विक्रेता जिले के सबौर थाना क्षेत्र के सरधो गांव निवासी दःखन तांती की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और सड़क जामकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। वहीं सड़क जाम की खबर मिलते ही घटनास्थल पर वरीय पलिस अधीक्षक हृदय कांत पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसएसपी ने बताया कि घटना में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और



उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अपराधी के इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। घटना में प्रयुक्त की गई हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। सत्संग के दौरान पुलिस की भी तैनाती थी, लेकिन पुलिस के जवान ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं किए इसको लेकर भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। पति भी चला गया। अब खून के बदले खुन का इंसाफ पत्नी मांग रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजन का रो रोकर बुरा हाल है।

भागलपुर के कपूरी सभागार जिला जदय कार्यालय में मंगलवार को जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्षा (महिला प्रकोष्ठ) डॉ भारती मेहता के नेतृत्व में नारी शक्ति रथ महिला संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे योजनाओं को जन-जन तक बताना और पहुंचाना है। इस मौके पर जदयू की प्रदेश महिला अध्यक्षा भारती मेहता ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में नीतिश कुमार के 19 सालों के कार्यकाल के बारे में कार्यकताओं के बीच चर्चा की गई। नीतिश कुमार ने महिलाओं के लिए कितनी योजनाओं को चला रखा है। उसके बारे में जन जन तक कैसे बताया जाए उसे पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 2025 से 30 फिर से नीतीश के विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप



से फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने राजद पर भड़कते हुए कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जानता राजद के कार्यकाल में होने वाले घिनौना कार्य से वाकिफ हैं। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां राजद 40 सीटों का दावेदारी करते थे। चार सीटों पर सिमट गई है। उन्हें विधानसभा चुनाव में इस बार जनता जीरो पर आउट करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महिला अध्यक्ष भारती मेहता, प्रदेश महासचिव अर्पणा कुमारी, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकसा परवीन, सोनी कुमारी, शालिनी कुमारी के अलावा जदयू भागलपुर इकाई के कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। उक्त आशय की जानकारी जनता दल युनाइटेड भागलपुर इकाई के जिला प्रवक्ता शहर मीडिया प्रभारी शैलेंद्र तोमर ने दी।

ट्रक के आमने-सामने की टक्कर के बाद विक्रमशिला सेतु पर लगा जाम

AGENCY BHAGALPUR : विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का लम्बा जाम मंगलवार की सबह देखने को मिला। आज सुबह दो वाहनों की सीधी टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि आज सबह करीब सात बजे नवगछिया से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और भागलपुर से नवगछिया की ओर जा रही ट्रक आमने-सामने से टकरा गई। इस टक्कर में दोनों ही टुक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। घायल एक ट्रक के चालक की स्थिति नाजक है। उस घायल ट्रक चालक को इलाज के

पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त टुक के टूटे पट्टी को मरम्मत करवाने का कार्य तेजी से कराना प्रारंभ किया। तब तक वन वे बनाकर यात्रियों को निकाला जा रहा था। तकरीबन 3 घंटे बाद सगमता से यातायात बहाल हो पाया। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हमें जानकारी हुई विक्रमशिला सेतु पर दो ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। फिर हम लोग यहां पर पहुंचे और घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजे हैं। उसके बाद यहां पर क्षतिग्रस्त टक की व्यवस्था

कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आयोजन समिति ने की बैठक

महावीर जयंती महोत्सव के आयोजन की शुरू हो गई तैयारी

AGENCY ARARIA फारबिसगंज के तेरापंथ भवन में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आगामी 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली 2624वीं जन्म जयंती महोत्सव कार्यक्रम को लेकर जन कल्याणक महोत्सव समिति की बैठक संयोजक बछराज राखेचा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में महावीर जयंती महोत्सव को भव्य एवं समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यक्रम के आयोजन और रूपरेखा को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सकल जैन समाज के तेरापंथ

सभा, साधु मार्गी जैन श्रावक



संघ, दिगंबर जैन समाज तथा जैन श्वेतांबर मंदिर मार्गी सभा के पदाधिकारी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में सर्वसम्मति से सुबह में प्रभात फेरी के रूप में एक शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया

महावीर के ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्रेरक प्रसंग पर आधारित कई झांकियो को सम्मिलित किए जाने

विचार किया गया।शोभायात्रा स्थानीय तेरापंथ भवन से प्रारंभ होकर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर वहां से समता भवन होते हुए श्री जैन श्वेतांबर पार्श्वनाथ जिनालय दादाबाड़ी पहुंचेगी और फिर वहां से तेरापंथ भवन पहुंचेगा। जहां भगवान महावीर से संबंधित एक धार्मिक संगोष्ठी होगी जिसमें भजन एवं एकांकी जैसे कार्यक्रम भी होंगे। इस अवसर पर जैन धर्मावलंबियों द्वारा प्रतिष्ठानों एवं आवास पर जैन ध्वज भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न उप समितियां भी बनाई गई।

परिवारवाद का प्रतीक है राजद, आरक्षण पर धरना सिर्फ राजनीतिक ढोंग : उमेश सिंह

लिए निजी अस्पताल में भर्ती

कराया गया है। देखते ही देखते

सड़क के दोनों और सैकड़ो

गाड़ियां का लंबा जाम लग गया।

लोगों को स्कूल, कॉलेज और

ऑफिस जाने में काफी परेशानियों

का सामना करना पड़ा। तत्परता

दिखाते हए यातायात डीएसपी

आशीष कुमार सिंह दलबल के

साथ घटनास्थल विक्रमशिला सेतु

जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को बयान जारी कर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के धरना-प्रदर्शन को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि राजद की राजनीति पूरी तरह परिवारवाद पर आधारित है, जहां लालू परिवार को सिर्फ अपने बेटे-बेटियों की चिंता रहती है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी गरीब, पिछड़े और वंचित समाज के हक-अधिकार की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि अब आरक्षण के नाम पर घड़ियाली आंस् बहाने वाले प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी



राजनीतिक सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा देश इस सच्चाई से परिचित है कि जातीय गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दुरदृष्टि और मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से यह चुनौतीपूर्ण कार्य न केवल सुगमता से संपन्न हुआ,

आंकड़े भी प्रकाशित किए गए। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर नीतीश सरकार ने शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही, हमें पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद 75 फीसदी आरक्षण का मार्ग भी शीघ्र ही प्रशस्त होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेता ने सामाजिक न्याय के साथ विकास की सोच को न केवल धरातल पर उतारा, बल्कि अपने 19 वर्षों के सफल शासनकाल में शोषित, वंचित और उपेक्षित तबकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया।

बल्कि निर्धारित समय पर इसके

क्या प्रधान पति, मुखिया पति सरपच पति की होगी छुट्टी

आधी आबादी की भागीदारी के बिना विकसित भारत का स्वप्न संभव नहीं है। महिलाएं देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लें, इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में उनकी भागीदारी आरक्षण द्वारा सुनिश्चित की गई। आज 33 से 50 फीसदी तक महिला आरक्षण राज्यवार दिया गया है। इसका उद्देश्य साफ था कि अंतिम जनों की आवाजों को प्रमुखता से सुनना, पर व्यवस्था की खामियों का क्या किया जाए, ये अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं। आज इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक बड़ी समस्या प्रधान पति, मुखिया पति, सरपंच पति बने हुए हैं। हालिया रिपोर्ट में भी यह समस्या उजागर की गई है कि कैसे महिला सरपंच के पुरुष प्रतिनिधि उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। पिछले दिनों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पूर्व खान सचिव सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित समिति ने एक रिपोर्ट मंत्रालय को पेश की है। इस समिति का गठन सितंबर, 2023 में किया गया था। पंचायती राज प्रणालियों और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं को बदलना। प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को खत्म करना शीर्षक वाली यह रिपोर्ट प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की बात जोर-शोर से उठाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों में महिलाओं की पारंपरिक और सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक मानसिकता और कठोर सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों को मनवाने से भी महिला प्रतिनिधित्व पीछे चला जाता है। इसमें एक है कई तरह की पर्दा प्रथाओं का पालन करना। रिपोर्ट में एक कारण राजनीतिक दबाव को भी बताया गया है, जिसमें राजनीतिक विरोधियों द्वारा मिलने वाली धमकी और दबाव भी है, जिसे न मानने पर उन्हें हिंसा का सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों के कारण उन्हें सार्वजनिक कामों से खुद को अलग करने का दबाव भी रहता है। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों के दबाव में वे अक्सर घर की जिम्मेदारियों को चन लेती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा कारण उनका अशिक्षित रह जाना भी है। बहुत सी सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक कामों के अनुभव न हो पाने के कारण वे निर्वाचित होने के बावजूद अपनी भूमिका सीमित कर लेती हैं। सबसे ज्यादा उन्हें वित्तीय निर्णय संबंधी कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे संबंधित पुरुष साथियों की मदद लेने को मजबूर हो जाती हैं। स्थानीय शासन में वास्तविक महिला नेतृत्व को मजबूत करने के मंत्रालय के लगातार प्रयासों के पक्ष में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसकी वजह है कि इसमें न केवल वास्तविक समस्या की पहचान की गई है बल्कि समस्या का समाधान भी प्रस्तावित किया गया है। इस कड़ी में मंत्रालय द्वारा साल भर चलने वाला सशक्त पंचायत नेत्री अभियान' है, जिसे देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह पंचायती राज पदों पर निर्वाचित महिलाओं के कौशल और आत्मविश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही हैं कि नहीं। इस रिपोर्ट में इस समस्या से निपटने के लिये कुछ सुधारात्मक दंड की सिफारिशें की गई हैं। ताकि प्रधान पति, सरपंच पति या मुखिया पति की प्रथा पर रोक लगाई जा सके। देश की पहली एमबीए सरपंच राजस्थान के टोंक जिले से सोदा गांव की छवि राजावत थीं, जो 2010 में सरपंच बनीं और महिला सशक्तीकरण के लिए काम किया था। अपने एक लेख में कहती हैं कि मेरा केस अपवाद हो सकता है। आज भी देश में बहुत सी निर्वाचित महिला सरपंच शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे के सामान्य ज्ञान की कमी से जुझ रही हैं। परिणामस्वरूप वे अलग-थलग पड़ जाती हैं। इस कारण उनकी छोडी गई जगहों को भरने के लिये संबंधी परुष आगे आ जाते हैं। कछ मामलों में तो परुषों के सपोर्ट को निर्माण परियोजनाओं में मार्गदर्शन प्रदान करने या काम की निगरानी करने या फिर उन्हें सरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सही ठहराया जाता है। इस नेक इरादे के बावजूद यह प्रयास महिला आरक्षण के उद्देश्य को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के कारणों को गौर किया जाए तो वे सभी वहीं कारण हैं, जिनकी वजह से महिलाओं को घर के बाहर सार्वजनिक भूमिका को स्वीकारा नहीं जाता है। स्वीकारने से पहले उनकी सार्वजनिक भिमका को ही नकारने की प्रवृत्ति रहती है, जो उनकी राह में कई तरह की बाधाओं के रूप में सामने आती है। पंचायती शासन प्रणाली को लागू हुए 31 वर्ष हो चुके हैं। महिला प्रतिनिधियों को किसी न किसी बहाने उन्हें उनकी पारंपरिक भूमिका में सीमित करने की मानसिकता में ऐसे ही किन्हीं सरकारी प्रयासों से कुछ संभव हो सकता है, यह आगे हम सबके

ट्रंप के टैरिफ से आया दुनिया में नया आर्थिक भूचाल **3** मेरिका में इस बार चुनाव के दौरान ही ट्रंप के आकारक के



आखिर टैरिफ है क्या, जिससे ट्रंप की घोषणा के बाद बडा वैश्वक भूचाल आया हुआ है। यह दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। इसका भूगतान आयातक करते हैं। किसी वस्तु पर 10 फीसदी टैरिफ का मतलब भारत से अमेरिका पहुंची 5 डॉलर की उस वस्तु पर 0.50 डॉलर का अतिरिक्त टैक्स है। इससे आयातित वस्तु का दाम बढता है और खरीददार सस्ते घरेलू उत्पाद ढूढ़ने लगते हैं। नतीजतन आयात करने वाले देश को अपनी अर्थव्यवस्था बढाने में सहयोग मिलता है. लेकिन टंप का नजरिया अलग है। वो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने, नौकरियों की रक्षा करने और कर राजस्व बढाने के तौर पर देखते हैं। दुनिया के अमीरों में शुमार दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के शेयर बाजार की चाल को नियंत्रित करते हैं, वे भी ट्रंप के इस कदम से नाखुश हैं। बफेट टैरिफ नीतियों को युद्ध जैसा कदम मानते हैं। महंगाई और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की आशंकाएं जताते हैं। इससे दीर्घकालीन अवधि में आर्थिक प्रभावों पर दष्प्रभाव तथा आम उपभोक्ताओ पर बोझ बढ़ने की आशंका जताते हैं। बफेट की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ट्रंप के चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ बढाने की घोषणा के बाद आई।

थे कि वो न केवल कुछ नया करेंगे, बल्कि सभी राष्ट्रपतियों से बड़ी लकीर खीचेंगे। 13 जुलाई 2024 को उन्हें मारने की कोशिश के दौरान चली गोली ने पूरे चुनावी रुख को बदल डाला। मौत और ट्रंप के बीच का सेकेंड्स से भी कम का ये फासला ही कहीं उनके सख्त तेवरों की वजह तो नहीं। उनके मुंह से तब निकले-फाइट, फाइट, फाइट के शब्द अब हकीकत में दुनिया के लिए चुनौती बन रहे हैं। ट्रंप कड़े और बड़े फैसले लेकर सबसे फाइट कर रहे हैं। क्या उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिका और दुनिया में नया इतिहास रचेगा। सबसे ज्यादा परेशानी और हैरानी उनकी हालिया टैरिफ घोषणाओं से है जो दुनिया में चिंता का सबब है। आखिर टैरिफ है क्या, जिससे ट्रंप की घोषणा के बाद बड़ा वैश्विक भूचाल आया हुआ है। यह दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। इसका भुगतान आयातक करते हैं। किसी वस्तु पर 10 फीसदी टैरिफ का मतलब भारत से अमेरिका पहुंची 5 डॉलर की उस वस्तु पर 0.50 डॉलर का अतिरिक्त टैक्स है। इससे आयातित वस्तु का दाम बढ़ता है और खरीददार सस्ते घरेलू उत्पाद ढूढ़ने लगते हैं। नतीजतन आयात करने वाले देश को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सहयोग मिलता है, लेकिन ट्रंप का नजरिया अलग है। वो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने, नौकरियों की रक्षा करने और कर राजस्व बढाने के तौर पर देखते हैं। दुनिया के अमीरों में शुमार दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के शेयर बाजार की चाल को नियंत्रित करते हैं, वे भी ट्रंप के इस कदम से नाखुश हैं। बफेट टैरिफ नीतियों को युद्ध जैसा कदम मानते हैं। महंगाई और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की आशंकाएं जताते हैं। इससे दीर्घकालीन अवधि में आर्थिक प्रभावों पर दुष्प्रभाव तथा आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की आशंका जताते हैं। बफेट की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ट्रंप के चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा के बाद आई। इससे ग्लोबल टेड वॉर

और बढा जो निवेशकों की गहरी चिंता का सबब है। टैरिफ पर अमेरिका और चीन आमने-सामने हैं। चीन चेतावनी दे चुका है। कि वो इससे निपटने के लिए तैयार है। चीन ने कह चका है कि वह अमेरिकी दबाव का मुकाबला करेगा। चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढते ही दिनया की दो दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार युद्ध के आसार झलकने लगे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग का बयान कि यदि कोई देश केवल अपने हित आगे बढाने लगे तो दुनिया में जंगल का कानून लागू हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका को फेंटेनाइल महामारी से निपटने में बीजिंग का सहयोग नहीं भूलना चाहिए। क्या वाशिंगटन इस उदारता का बदला अकारण टैरिफ बढ़ा ले रहा है? सच है कि चीन लंबे समय से विश्व का कारखाना बना हुआ है। 1970 के आखिर में जैसे ही चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोली तबसे सस्ते श्रम और बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश के चलते ऊंचाइयां छूता चला गया। शायद ट्रंप को यही चीनी सफलता चुभ रही हो। दुनिया की निगाहें ट्रंप के टैरिफ युद्ध खासकर चीन की मैन्युफैक्करिंग इंडस्ट्री पर है कि उसे कितना नुकसान पहुंच सकता है।

दिखते हैं। टैरिफ उनके इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा है। इससे अमेरिकी मैन्युफैक्करिंग और रोजगार बढ़ेंगे। गौरतलब है कि उनके खास मित्र एलेन मस्क भारत में संभावनाओं को खोज ही रहे थे कि ट्रंप की सत्ता वापसी हुई। माना कि मस्क की टेस्ला कार की कीमत एक करोड़ होगी। उस पर भारत में उतना ही टैरिफ लगेगा, जिससे यहां कीमत दो करोड हो जाएगी। यदि दबाव के चलते कहीं शन्य टैरिफ वाली स्थित बनी तो वही कार एक करोड़ में भारत में मिलेगी। इससे भारतीय कार बाजार को जबरदस्त चुनौती तय है। यकीनन बात बहुत बिगड़ चुकी है। भारत समझता है कि ट्रंप जब कनाडा, यूरोपीय देशों और चीन को नहीं बख्श रहे तो भारतीय हितों व सम्मान की रक्षा खद करनी होगी। वहीं, ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के पहले संयक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। इसमें भारत का नाम फिर उन देशों के साथ लिया, जिन्होंने अपनी ऊंची शुल्क दर से नरम अमेरिकी नीतियों का फायदा उठाया। अमेरिका आगामी दो अप्रैल से इन देशों पर जैसे को तैसा या 'आंख के बदले आंख' की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। जो देश जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही अपने यहां लगाएगा। इससे भारतीय एक्सपोर्ट महंगा होगा। खाद्य फार्मास्युटिकल्स और ऑटोमोबाइल सामग्रियां अमेरिकी बाजार में महंगी होंगी। नतीजन भारतीय उत्पाद वहां अभी जैसे नहीं टिक पाएंगे। 1951 में अमेरिकी संविधान में 22वें संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति दो बार राष्ट्रपति रह सकता है। टंप आखिरी टर्म में वो कर गजरना चाहते हैं जो इतिहास बने। वहीं, उनके व्यापारी मित्र अपने व्यापारिक हितों में लिपटे दिखते हैं। टंप की मंशा को समझना आसान भी नहीं क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि अगले पल क्या कर गुजरेंगे। जिद्दी ट्रंप किसी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं मानते। न यही बताते कि पुराने अमेरिकी प्रशासनों ने ऐसे देशों को क्यों ऊंची दर से शल्क लगाने दिया। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप और युक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच प्रेस कांफ्रेन्स के दौरान कैमरों पर जो अप्रिय विवाद दिखा, जिसकी हर तरफ निंदा हुई। शांति की कीमत के बदले ट्रंप की यूक्रेनी खनिज भंडारों पर कब्जे की मांग यकीनन निंदनीय है। ट्रंप की नीयत ही बदनीयत लगती है। कहीं वो दुनिया को नए ट्रेड वार में धकेल कर उससे भी कमाने का रास्ता तो नहीं खोज रहे।

राजस्थान दिवस वर्ष प्रतिपदा पर मनाने का निर्णय

दुसरी ओर ट्रंप इस बार अपने व्यापारी मित्रों,

सहयोगियों और सलाहकारों से ज्यादा घिरे

वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था कि यदि हमें गौरव से जीने की भावना जागृत करनी है और यदि हम अपने हृदय में देशभक्ति के बीज बोना चाहते हैं तो हमें हिंद राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का आश्रय लेना होगा। जो कोई भी विदेशियों की तिथियों पर निर्भर रहता है वह गुलाम बन जाता है और आत्मसम्मान खो देता है। स्वामी विवेकानंद की यह उद्घोषणा भारतीय संस्कृति और काल गणना के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही भारत के नीति निमार्ताओं को भी मार्गदर्शन देती है कि उन्हें राष्ट्र और समाज के उत्थान और उसके आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए। हाल ही राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राजस्थान का स्थापना दिवस भारतीय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने की घोषणा की है। विधानसभा के पटल पर रखा गया मुख्यमंत्री भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित तौर पर इससे राजस्थान दिवस जनता का उत्सव बन सकेगा। गौरतलब है कि भारतीय नववर्ष मनाने के लिए गठित नववर्ष समारोह समिति गत 24 वर्षों से राजस्थान सरकार से लगातार मांग कर रही थी कि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के बजाय वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर पर मनाया जाए। इसके पीछे उनका तर्क है कि राजस्थान की स्थापना हिंदू पंचांग के अनुसार इसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर हुई थी। उस दिन 30 मार्च थी। बाद में वर्ष प्रतिपदा को भुला दिया गया और 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख

भाषण में तब उन्होंने कहा था-राजपुताना में आज नए वर्ष का प्रारंभ है। यहां आज के दिवस वर्ष बदलता है। शक बदलता है। यह नया वर्ष है। तो आज के दिन हमें नए महा राजस्थान के महत्व को पर्ण रीति से समझ लेना चाहिए। आज अपना हृदय साफ कर ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें राजस्थान के लिए योग्य राजस्थानी बनाये। राजस्थान को उठाने के लिए राजपूतानी प्रजा की सेवा के लिए ईश्वर हमको शक्ति और बुद्धि दे। आज इस शुभ दिन हमें ईश्वर का आशीर्वाद मांगना है। मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरे साथ राजस्थान की सेवा की इस प्रतिज्ञा में इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। जय हिंद। वल्लभ भाई पटेल के भाषण की बातें राजस्थान का स्थापना दिवस समारोह वर्ष प्रतिपदा जैसे शुभ अवसर पर आयोजित करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय नववर्ष महज तिथि का बदलना

नहीं है। यह वह अवसर है, जब प्रकृति पूरी तरह सजधज कर दुल्हन का सा स्वरूप धारण करती है। वसंत ऋतु की शुरूआत होती है, जब पेड़-पौधों में नए पत्ते और फूल खिलते हैं। वातावरण में उत्साह का संचार होता है। इसका खगोलीय महत्व है, जिसका विस्तार से वर्णन शास्त्रीय परंपरा में है। वर्ष प्रतिपदा एक खगोलीय गणना है, जो ब्रह्मांडीय घटनाओं से जडा हुआ है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पृर्ण चक्र पूरा करती है। इस दिन दिन-रात बराबर होते हैं, जो संतुलन और नए जीवन का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इस दिन से जुड़ी है, जो सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को प्रेरणा देती है। राजा विक्रमादित्य ने इसी दिन विक्रम संवत की स्थापना की थी। भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। यह सिखों

जन्मदिन भी है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तब यहां अनेक रियासतें थीं, जिन्हें मिलाकर यह राज्य बना। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसकी शुरूआत 18 अप्रैल 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों के विलय से हुई। विभिन्न चरणों में रियासतें जुड़ती गईं तथा अन्त में 1949 में वर्ष प्रतिपदा (30 मार्च) के दिन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से वहत्तर राजस्थान संघ बना। इसे ही राजस्थान स्थापना दिवस कहा जाता है। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की सिक्रय

रियासतों को भारतीय प्रतिपदा पर मनाने ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक रूप से पूर्णतः उचित है। यह केवल एक तिथि परिवर्तन नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान, स्वाभिमान और गौरवशाली परंपराओं पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरदार पटेल के शब्दों को याद रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह निर्णय राजस्थान को गौरवशाली अतीत से जोड़ते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा। पुनश्चः जन्म कुंडली और विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार हम ग्रह-नक्षत्रों की दिशा पर आधारित तिथियों के अनुसार तय करते हैं, लेकिन अपनी सविधा के लिए उनकी वर्षगांठ के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर निर्भर हो जाते हैं।

Social Media Corner

सच के हक में.

कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू-कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के

निर्माण के सपने की बड़ी जीत है। (गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को ४ प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस पार्टी के मंत्री डी. के. शिवकुमार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान तक बदलने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही संविधान विरोधी रहा है। कांग्रेस प्रारंभ से ही संविधान में

छेड़छाड़ करती आई है। (पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

और वह डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। उम्मीद है कि इससे उसकी गिरावट से चिंतित लोगों को राहत मिली होगी और उसे लेकर शुरू हुई बहस थमेगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि रुपये के मुल्य में गिरावट का एक दीर्घकालिक इतिहास है। 1947 में इसकी विनिमय दर प्रति डॉलर 3.30 रुपये थी, जो 1980 में गिरकर 7.8 रुपये, 1990 में गिरकर 17.01 रुपये और 2000 तक आर्थिक उदारीकरण के बाद यह और गिरकर 43.50 रुपये हो गई। फिर एक दशक बाद 2010 में यह 46 रुपये पर थी और 2020 में गिरकर 71 रुपये पर पहुंच गई। सितंबर 2021 से इसकी विनिमय दर 73 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर बीते दिनों 87 से अधिक हो गई। रुपये में गिरावट एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। जो भी विपक्ष में होता है, वह रुपये के गिरने के लिए सरकार को ही दोषी ठहराता है, लेकिन रुपये में गिरावट के इन सभी दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। हमें यह सोचना बंद करना होगा कि रुपये में गिरावट का मतलब अर्थव्यवस्था का कमजोर होना है। गिरते रुपये का राष्ट्रीय गौरव से भी कोई संबंध नहीं है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। जब कोई देश दुनिया के साथ व्यापार करता है तो उसकी मुद्रा की विनिमय दर का इस व्यापार पर गहरा असर होता

है। रुपये के गिरने का मतलब है कि भारत के

ते कुछ दिनों से रुपये की गिरावट थमी है निमार्ताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी वस्तुओं को बेचना आसान होगा, क्योंकि वे इन्हें डॉलर में बेचेंगे. लेकिन उनकी लागत रुपये में होगी। यही बात आईटी जैसी सेवा क्षेत्र की कंपनियों पर भी लागू होगी, जो अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवा देती हैं। अधिक निर्यात का मतलब रोजगार के बेहतर अवसर सुजित होना है। रुपये की कम कीमत भारत आने वाले पर्यटकों को भी बढ़ावा देती है। यह विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले पैसे या वेतन के मूल्य को भी बढ़ाता है, लेकिन रुपये में गिरावट का आयात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा वह और महंगा हो जाएगा। भारत सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम पदार्थों का करता है, जिसकी मांग स्थिर रहती है और कीमत के साथ नहीं बदलती। इसी तरह हम सोने का भी आयात करते हैं, जिसकी कीमतें पहले से ही ऊंची हैं। इसके अलावा इससे भारतीयों का विदेश में अध्ययन करना या पर्यटन करना भी महंगा हो जाएगा। ट्रंप की नई अमेरिकी सरकार टैरिफ के जरिये दूसरे देशों पर दबाव डाल रही है। यह भारत या अन्य देशों से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर टैक्स है। इससे अमेरिकी बाजार में हमारे निर्यात महंगे हो जाएंगे। इस समस्या को संतुलित करने और हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाने में रुपये में गिरावट एक जरूरी सहारा बन सकता है। कम विनिमय दर वाला रुपया

रुपये के गिरने-चढ़ने का मतलब

मेक इन इंडिया मिशन में भी मदद करेगा। अब तक मेक इन इंडिया के बैनर तले मोबाइल फोन जैसे कई उपभोक्ता सामान मुख्य रूप से चीन से पुर्जे आयात करके भारत में उन्हें असेंबल करने पर आधारित हैं। इससे कंपनियां सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का लाभ तो उठा लेती हैं, लेकिन यह स्वदेशीकरण के पैमाने पर अधुरा है। जब डॉलर महंगा हो जाएगा, तो चीन से ऐसे पुर्जे आयात करना और महंगा हो जाएगा। इससे कंपनियां अपने सभी पुर्जे भारत में ही बनाने को प्रेरित होंगी। इससे देश में शोध एवं विकास के साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे। अन्य देशों के अनुभव बताते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन हमेशा बुरा या अच्छा नहीं होता। दरअसल मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव देश की आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। इस सदी के शुरूआती वर्षों में चीन ने जानबुझकर अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के मुकाबले लगभग 30 प्रतिशत कम कर दिया। ऐसा अवमूल्यन चीनी वस्तुओं को विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता रखने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निर्यात को सस्ता बनाने की इस नीति ने चीनी निमार्ताओं को वैश्विक बाजारों में बढ़त हासिल करने में मदद की। नतीजतन उस अवधि के दौरान चीन के निर्यात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उस अवमूल्यन ने चीन की निर्यात मात्रा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद की, जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्षुद्र राजनीति

निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई सिमति (जेएसी) की पहली बैठक के लिए चेन्नई में 22 मार्च को प्रभावशाली जुटान हुआ। इसमें चार मुख्यमंत्रियों समेत कई राज्यों के नेता साथ आए। इस बैठक ने एक स्पष्ट संदेश भेजा। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित कोई भी परिसीमन कवायद अस्वीकार्य है। बैठक की मुख्य मांग थी- साल 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों की जो संख्या स्थिर (फ्रीज) की गई है उसे और 25 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए। इसी तरह का प्रस्ताव तमिलनाडु में राजनीतिक दलों की एक हालिया बैठक में भी पारित किया गया था, जिसमें 30 साल के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था। सीटों की संख्या स्थिर रखने की संकल्पना नई नहीं है। इसे 42वें संशोधन के जरिए लागू किया गया (साल 2000 तक) और 84वें संशोधन के जरिए विस्तारित किया गया (साल 2026 तक)। जेएसी ने उचित रूप से जोर दिया कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन सफलतापूर्वक लागू किया, उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व घटाकर सजा नहीं दी जानी चाहिए। खास तौर पर दक्षिण में प्रमुखता के साथ नजर आने वाली इस चिंता को एक क्षेत्रीय मुद्दे के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए, भले ही बैठक में दक्षिण की मजबूत उपस्थिति थी, जिसकी मेजबानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शिरकत की। बैठक में दक्षिण के बाहर से भी भागीदारी देखी गई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल हैं। ऑनलाइन संबोधन में पटनायक ने प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए राज्यों को दंडित किए जाने के खिलाफ संदेश को मजबूती दी। एक लंबे अरसे बाद विभिन्न क्षेत्रों व विचारधाराओं के राजनीतिक दल मौकापरस्त चुनावी गठबंधन (जिनमें नीतिगत एकरूपता नहीं होती) बनाने के बजाय एक महत्वपूर्ण मुद्दे प्रतिनिधिक लोकतंत्र पर एकजुट हो रहे हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail: thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The government must mainstream natural, organic and regenerative farming to realise food and ecological security.

It's time natural and regenerative farm practices were revived

Myriad hurdles impede course of justice

Former Chief Justice of India (CJI) NV Ramana was rather critical of our justice delivery system in his speech on a public platform last week. He is reported to have said that an average citizen is apprehensive about approaching courts, fearing the unknown. Concerns have been raised about delays, pendency, accessibility, deficient infrastructure, a large number of vacancies, (lack of) transparency in legal proceedings, an illequipped criminal justice system and an increasing count of false cases. That's quite a handful of problems faced by our justice delivery system. It begs the question: What is being done to tackle the citizen's apprehension about approaching courts and what is being done to address the problems pointed out by the ex-CJI?It is a matter of common knowledge, and this can easily be verified from the National Judicial Data Grid, that the number of cases pending in the district courts and high courts across the country has crossed a staggering 5.1 crore, with a few lakh cases pending for more than 20 years. This is shameful and was sarcastically described as intergenerational justice. There are several alternatives that are available for managing the caseload, but, unfortunately, there does not seem to be any will to do so. For example, petty criminal cases can be resolved through plea bargaining, a mechanism that is available in our criminal procedure. Civil cases, including some complicated ones, can be resolved through mediation, as recognised by our civil procedure. Parliament enacted the Mediation Act in 2023, but the Mediation Council has not yet been established. A law to establish Gram Nyayalayas was enacted in 2008, but 17 years down the line, it has not been fully implemented across the country. A few hundred Gram Nyayalayas have been established, but almost half of them are non-functional. Unless we implement the laws enacted by Parliament in their true spirit, the problem of a large number of pending cases will continue until the justice delivery system collapses under the weight of the caseload.

Judges' posts lying vacant is another perennial problem. It is estimated that the number of vacant positions in high courts is about 30 per cent, while the number in district courts is about 22 per cent. Why is it so difficult to fill these vacancies? It is not that there is a shortage of qualified lawyers, but again the will to fill vacant posts is missing. Anecdotal evidence suggests that lawyers are not inclined to become judges because the salary is somewhat inadequate and there are pressures such as the possibility of a sudden transfer from the place of work, frivolous complaints being filed against judges with a view to demoralise them and so on. These issues require serious consideration; otherwise, a time will come when it will be difficult to appoint qualified lawyers as judges. The large percentage of vacancies is not a new phenomenon — it has been continuing for several years and will persist unless the decision-makers get their act together and fill the vacancies with well-qualified lawyers by improving their service conditions. Infrastructure has always been a huge problem for the judiciary. In some states, if the full complement of judges is appointed, there will be no room for them to hold court or the space would be inadequate, adding to their inconvenience. Having visited district courts in several states across the country, I can confidently state that there is a lot that needs to be done to upgrade infrastructural facilities. While there is a massive move to improve infrastructure across the country in terms of roads, buildings and so on, there is hardly any movement to make courts better, except in large cities. This needs to change, and change urgently. One of the problems facing the justice delivery system, generally, is the absence of adequate budgetary allocation. A study conducted by the India Justice Report points out that the allocation is less than 1 per cent of the state's budget. It is well known that a large amount of the budgetary allocation goes on payment of salaries. There is hardly anything left for improving infrastructure, not only in terms of buildings but also in terms of facilities for the litigants such as chairs in the courtroom and provision of services related to litigation.

The National Food Security Act (NFSA) in India states that the right to food must be implemented to guarantee food to the needy people at affordable prices. Thus, food security is of great concern to India. With its population, currently at 143 crore, which is likely to expand to 160 crore by the 2060s, food security will remain the one of the top policy agendas. One way to fulfil this demand is to further intensify agriculture, which is already under pressure due to a substantial decline in fertiliser efficiency, deteriorating soil health, climate change and over-exploitation of water resources. According to a recent Food and Agriculture Organisation report, intensive agriculture is causing huge economic damage globally. The social, health and environmental cost of In India, with its centuries-old practice of natural farming

intensive agriculture and associated food systems in India is estimated to be a Rs 113 lakh crore (\$1.3 trillion) annually. The other approach is to examine alternative systems that have been part of the agriculture and farming communities since the pre-modern agricultural period, modify them using science-based agroecological principles, examine their feasibility and upscale them to secure the future of sustainable farming. This will ensure food and ecological security by improving farm productivity and farmers' profitability, protecting natural resources and improving soil health and biodiversity.Indian agriculture must widen its vision. It should not just rely on intensive agricultural practices through input subsidies, which started in the 1960s during the Green Revolution and are causing damage to society and planetary health. It must mainstream natural,

organic and regenerative farming to realise food and ecological security. Currently, a fraction of the farmers practise natural, organic or regenerative farming. The time is right to understand and evaluate these different systems so that the agricultural landscape can be diversified, strengthened and made future-proof.

It is not widely recognised that natural farming originated in India. This was noted by Sir Albert Howard, an imperial economic botanist and director of the Institute of Plant Industry, Indore, during his service between 1905 and 1931 in India. It was also known as the Indore process. Sir Howard described natural farming as a system that follows the cycles of nature to produce food. It aims to produce food holistically by maintaining a balance between crop and soil health and focusses on the well-being of farmers and consumers. Sir Howard

by financial constraints, bureaucratic red tape and a

lack of awareness. Regulatory hurdles, complex

approval processes and inconsistent enforcement of

formalised the principles of natural farming. Today, less than one million hectares are under natural farming, practised by about 2.2 million farmers, predominantly small farmers. Ironically, intensive farm practices were adopted in the 1960s, overlooking the sustainable practices that were locally developed and embedded for centuries. The principles of natural farming also inspired Lady Eve Balfour and Jerome Rodale as they pioneered organic farming movements in the UK and the USA respectively in the mid-20th century. The term natural farming 1979 onwards was re-popularised by Japanese farmer and philosopher Masanobu Fukuoka as the science of growing food naturally.



was popularised by Subhash Palekar, who initiated the movement for zero-budget natural farming around the turn of the century. Organic farming prohibits synthetic inputs, such as chemical fertilisers, genetically modified seeds, growth hormones and antibiotics. The organic movement began in the early 20th century. Organic food is grown using the principles primarily based on standards advocated by the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). The IFOAM-Organics International works in over 100 countries.In India, about 2.7 million hectares are under certified organic farming. It is an extension of natural farming, but comes with a third-party certification of authenticity and, hence, a price premium in the market. Food produced using natural farming does not require certification. The term regenerative farming was coined

by the Rodale Institute, USA, in 1980 and has become popular during the last five years. However, the practices of regenerative farming existed long before, as Sir Howard founded them in the early 20th century in India. It is defined as the system of food production that promotes the judicious use of inputs, promotes farmers' well-being and focusses on improving human and soil health. It aims to conserve resources and provide a rehabilitation approach to producing food by improving soil, land, water and biodiversity. These farming systems originated in India when Sir Albert Howard described the local, sustainable farming systems as natural farming systems. Comparing and contrasting these systems allows us to conclude that regenerative and natural

farming are highly productive systems, with better social and ecological outcomes.

These systems are being adopted in farms worldwide. They can offer millions of farmers in India an alternative to improving climate resilience and increasing their incomes while producing enough food required for the nation's food security.Organic farming, which is distinguishable from local inputs-based natural farming, is often co-related with high consumer prices. It has its place with conscious consumers who have the buying power and support a responsible food production system.

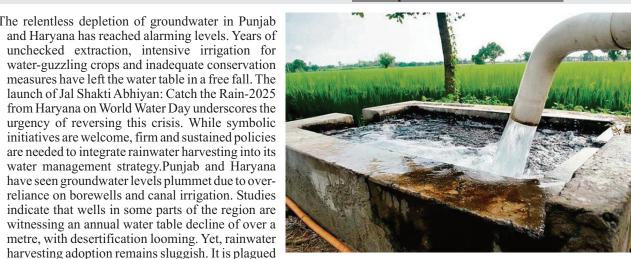
As much of the agricultural land in India is under intensive agricultural practices, there is a need to re-examine the role of natural, regenerative farming across all agroclimatic zones. An appropriately diversified approach can be adopted based on the geography and social and ecological

conditions. This will help achieve a rapid uptake of natural or regenerative farming practices and enable agricultural diversification and adoption of sustainable and equitable farming systems.

The recently launched National Mission on Natural Farming by the Government of India is a step in this direction. The government has set the goal of adoption of natural farming by 10 million small farmers by 2026. Once it is achieved and replicated at scale, it will improve the livelihoods of millions of farmers and enhance the climate resilience of farms. Millions of consumers will have access to food grown responsibly and free from harmful chemicals. Following such policies, India must redesign its agriculture with a clear strategy to mainstream natural, organic and regenerative farming to secure its food and ecological and nutritional security.

Catching the rain

Bold steps needed for its enforcement



rainwater harvesting mandates further deter its widespread implementation. To combat this, Haryana's Mukhyamantri Jal Sanchay Yojana and initiatives like

the Integrated Water Resource Action Plan (2025-27) must go beyond tokenism. A clear roadmap, backed by financial incentives and technological innovation, is crucial. Property tax rebates for households implementing rainwater harvesting, as seen in Indore, should be replicated across north India. Additionally, urban planning must integrate rainwater harvesting into building codes, ensuring that new developments contribute to groundwater recharge. Rural outreach is equally vital. Equip farmers with knowledge of efficient irrigation techniques to reduce their dependence on groundwater. Solar-powered micro-irrigation projects, as launched in Haryana, should be expanded to Punjab. Moreover, reviving traditional water bodies and desilting village ponds can aid in water retention and

percolation. Water scarcity is no longer a distant threat

— it is a present crisis.

IPKF martyrs must be properly honoured

Why are the IPKF martyrs not being officially recognised and properly honoured and its veterans only allowed a silent felicitation? The reason is politics.

Today (March 24) is the 35th anniversary of the return of the Indian Peace Keeping Force (IPKF) from its mission in Sri Lanka (Operation Pawan). It was India's first expeditionary force designed to end the ethnic conflict in the Emerald Isle, following the India-Sri Lanka Accord (ISLA) of July 29, 1987 — the date Op Pawan, the military component of the

ISLA, commenced.

Change of governments in both Sri Lanka and India resulted in double jeopardy: recall of the IPKF without being permitted to complete its mission. While the IPKF achieved a number of its military objectives in a brief 32 months, the political and diplomatic tracks failed to keep up. As many as 1,157 Indian soldiers sacrificed their lives and 3,009 of all ranks were wounded to maintain the sovereignty and territorial integrity of Sri Lanka.

Sri Lanka built a memorial for the IPKF in Colombo; one was already there in Jaffna. At both memorials, on India's Republic and Independence Days, commemoration ceremonies are jointly held by Indian and Sri Lankan government officials. In January 2025, the Sri Lankan Army Chief, Lt Gen Lasantha Rodrigo, laid a wreath at the Jaffna memorial. Each time Indian dignitaries, including PM Narendra Modi, visit Colombo, they lay a wreath at the IPKF memorial.

But none of this happens at the National War Memorial (NWM), Delhi. Today, some 150 Op Pawan veterans and their families will gather at the NWM for an Army HQdesignated 'silent felicitation'. Silent means no playing of the Last Post and Rouse by bugles to honour the martyrs, making the ceremony incomplete. Adjutant General's letter of January 14, 2025, says: "No felicitation ceremony will be permitted during conduct of above event."This is, therefore, a private event organised by the IPKF veterans who have been fighting protracted battles with the military bureaucracy and the MoD for the last four years, involving three Army Chiefs - Generals Naravane, Pande and Dwivedi. The first two Generals are IPKF veterans. Letters written to the PM,



the Raksha Mantri and the Military Adviser to RM have elicited no joy. A typical bureaucratic reply from the Integrated Defence Staff of the MoD received on October 17, 2024 reads: "The IPKF's case for official recognition is under active consideration. The case for earmarking a day for commemoration of Op Pawan was deliberated by a tri-service committee in detail which decided to maintain status quo."The IPKF veterans saw a sliver of hope when the Army Chief, General Dwivedi, in an interview with ANI in February, mentioned with high emotion the LTTE ambush of 13 Sikh LI in Jaffna, when the company was wiped out; only one soldier was spared to tell the story.

Appeals made by the Indian Ex-servicemen Memorial League and senior officers for the official recognition of the IPKF have fallen on deaf ears. The NWM in Delhi is conspicuously incomplete in documenting the synopses of wars and skirmishes fought since 1947. Only two actions - Kargil 1999 (Op Vijay) and India-China Border Conflict 1962 — are inscribed on Rajasthan stone markers. On top of the Op Vijay marker, Op Pawan is inscribed, with two arrows pointing in opposite directions. But there is no Op Pawan marker or any other marker. This lapse must be corrected.

Last year in Dehradun, CDS Gen Anil Chauhan told IPKF veterans: "We have fought hundreds of operations; Op Pawan was only a minor operation." By no stretch of imagination can Op Pawan be called 'minor'. It was the longest, intensely fought campaign, where the IPKF suffered heavy casualties. Equally, it won several gallantry awards — UYSM, one; PVC, one; MVC, three; VrC 98; and 250 other bravery medals. The last of the IPKF left Sri Lanka on board INS Magar from the Trincomalee harbour and arrived in Chennai (then Madras) on March 24, 1990. It was welcomed with banners bearing the ITKF (the Indian Tamil Killing Force). As the then PM VP Singh could not come to Madras to welcome the IPKF, they were flown in IL76 to Palam to be felicitated by him.

Those were difficult days, with Kashmir and Khalistan uprisings at their peak. The IPKF was quickly sucked in to counter them. The official recognition of Op Pawan was put on the back burner; so also, the After Action Report and Lessons Learnt. The report has not been declassified.

Why are the IPKF martyrs not being officially recognised and properly honoured and its veterans only allowed a silent felicitation? The reason is politics. When the IPKF returned from Sri Lanka, a DMK government was in power in Tamil Nadu and a part of the coalition at the Centre. When the LTTE was defeated in 2009, the DMK was again in power. The domestic Tamil factor weighed heavily in India's Sri Lanka policy due to the DMK having 29 MPs in the UPA government. Today, the ruling BJP is desperate to breach the DMK's cordon sanitaire in the south and secure a toehold after the 2026 elections. It is doing everything to win over the Tamils, in Singapore, Jaffna and south India. In January, the Jaffna Cultural Centre was renamed Thiruvalluvar Cultural Centre after the Tamil Nadu author of the legendary treatise, Kural. Jaffna Tamils objected to this. A compromise name was found: Thiruvalluvar Cultural Centre Jaffna.

The DMK apparently has not softened towards the IPKF. On November 25, 2024, Lt Gen KS Brar, GOC Dakshin Bharat Area, organised a Bravery Day commemoration in Chennai to honour, among others, a PVC winner in Sri Lanka, Maj P Rameshwaran, from Tamil Nadu. Chief Minister Stalin, who was invited as chief guest, neither accepted nor declined the invitation but did a noshow. The DMK's hypocrisy during the last phase of the war in Sri Lanka is well known. For the time being, the IPKF will have to be content with a silent and unofficial commemoration. Abridging the commemoration protocol by not sounding the Last Post and Rouse is a big disservice to the IPKF martyrs.

Air India staff to fly economy as airline tackles passenger concerns: Report

New Delhi. Air India has mandated that all its staff, including senior management, will have to travel in economy class from April 1, reported The Times of India. The airline has made the decision to free up premium seats for paying customers. Employees will only be allowed to upgrade to premium economy or business class if those seats remain unsold 50 minutes before departure, added the report. The move is part of Air India's effort to improve its service and customer experience, following criticism over frequent flight delays. A spokesperson for Air India said the change was aimed at ensuring that premium seats, which are in high demand, are available for customers first. The airline wants to build a strong customer-first approach under its new management.

India's aviation market is one of the fastest-growing in the world, with domestic air travel increasing by 10-12% annually over the past decade, according to government data. With more people choosing to fly, airlines are under pressure to ensure better service and availability of seats. Air India, formerly a stateowned airline, was taken over by the Tata Group in 2022. Since then, the airline has been undergoing a major transformation. Last year, it merged with Vistara, a joint venture between Tata Group and Singapore Airlines.

The airline has already spent billions of dollars on its turnaround plan. This includes ordering new aircraft, rebranding with a new logo, and upgrading interiors for over half of its fleet. The latest decision to keep premium seats available for paying passengers is another step in Air India's strategy to enhance its image and efficiency.

What is Google tax that India is likely to scrap from April 1

New Delhi. Donald Trump's tariff threats have forced many countries to rethink their policies, and India is no exception. The tariff threats have led to changes in policies, and the latest in line is the government's move to scrap the 6% 'Google Tax'. India is likely to remove the 6% equalisation levy, often called the "Google tax," on online advertising services provided by foreign tech companies like Google and Meta. The tax will be scrapped from April 1, 2025, as part of amendments to the Finance Bill, reported news agency Reuters."This levy, introduced in 2016, was specifically designed to ensure that foreign digital service providers generating significant revenues from the Indian market contributed their fair share to the exchequer, despite not having a physical presence in India," said Tushar Kumar, Advocate, Supreme Court of IndiaHe explained that its primary objective was to level the playing field between domestic entities, which were subject to income tax, and foreign technology conglomerates, which operated through digital platforms without a tax nexus under conventional international tax principles.

WHY IS INDIA REMOVING GOOGLE TAX?

"The removal of this levy marks a shift in India's digital taxation framework and is perceived as a strategic move to ease trade frictions with the United States, which had persistently objected to the tax as being discriminatory against American technology giants such as Google and Meta," said Kumar.In the past, this levy placed an additional financial burden on foreign digital companies by requiring them to withhold and remit a 6% tax on revenues earned from online advertising services provided to Indian businesses."Consequently, these costs were often passed on to advertisers, thereby increasing digital marketing expenses for Indian enterprises.

Bank FD: These special schemes are set to end on March 31; suitable for you

Kolkata. Over the past few years, fixed tenure fixed deposits have been increasingly launched by banks with slightly higher rate of interest to attract depositors. About half a dozen such FD schemes are coming to an end at the end of FY25. Therefore, the deadline to take advantage of these higher rates of interest is March 31, 2025, which is only seven days away. Significantly, despite the much higher returns by equities and mutual fund and even precious metals such as gold and silver (especially as demonstrated in 2025 by the two metals), a large section of Indians repose a lot of trust on bank FDs. Personal investment strategists too recommend that a part of any portfolio should consist of fixed-income securities, a space in which FDs have prominent presence. All those who are risk-averse (such as retirees, senior citizens) park a large share of their funds into FDs. Let's have a look which are the bank FDs that are coming to a close on March 31, 2025. State Bank of India FD

Two of the FDs that are coming to a close on March 31, 2025 are from India's largest bank State Bank of India (SBI). SBI Amrit Vrishti is an FD with a maturity period of 444 days and it pays 7.25% rate of interest for general customers and 7.75% for senior citizens. The other fixed tenure FD from SBI is Amrit Kalash, which has a maturity period of 400 days and offers 7.10% for general customers and 7.60% for senior citizens. This special FD scheme, too, in ending on March 31, 2025.HDFC Bank FDIndia's biggest private sector lender, HDFC Bank, has a special FD that offers a rate of 7.35% to general depositors and 7.85%. This special FD has a fixed tenure of 35 months.Indian Bank FDsPSU lender Indian Bank has special FD schemes that are called IND Supreme 300 Days and IND Super 400 Days. These schemes offer preferential interest rates — the peak rate being 8.05% for super senior citizens (those above 80 years). These schemes are also coming to an end on March 31, 2025. Punjab and Sindh Bank special FDPunjab and Sindh Bank's has a few FDs with fixed tenures. These come with maturity periods of 333 days (interest rate 7.20% for general customers, 7.70% for senior citizens), 444 days (7.30% and 7.80%), 555 days (7.45% and 7.95%), 777 days (7.20% and 7.70%) and 999 days (6.65% and 7.15%). These schemes will be available till March 31, 2025.

Govt proposes abolition of 6% equalisation levy

This is a significant move in the context of the ongoing Indo-US bilateral trade talks, and the imminent threat of reciprocal tax, which is likely to come into force from 2 April, 2025.

New Delhi. The government has proposed the abolition of the 6% Equalisation Levy on online advertising in the Finance Bill 2025, reducing the tax burden on digital ad consumers and lowering costs on platforms like Google and Meta. If passed in parliament, the 6% Equalisation Levy would cease to exist from 1 April 2025.

This is a significant move in the context of the ongoing Indo-US bilateral trade talks, and the imminent threat of reciprocal tax, which is likely to come into force from 2nd April, 2025. The US government has

always termed the digital taxes levied by India as discriminatory, targeting mainly tech giants from the US. Last year, the government had scrapped a similar levy of 2% on digital ecommerce supplies and services. The latest announcement by the government is, therefore, construed as an attempt by

Donald Trump administration. This change would now reduce the costs for digital ad consumers, while lowering tax costs for digital advertising platforms such as Google and Meta, says Sandeep Jhunjhunwala, M&A Tax Partner at Nangia Andersen. "Consequently, the corresponding income tax exemption under Section 10(50) has been withdrawn to maintain tax neutrality, meaning income previously exempt under the Equalisation Levy regime will

the government to appease the

provisions," he added. The government introduced the 6% Equalisation Levy in 2016.

now be taxed under regular income tax

The removal of the levy is seen as a move

towards aligning with the uniform tax rules under two pillar solutions proposed by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Currently, digital companies based outside the tax jurisdiction of a country escape paying taxes on revenue earned from that country. Pillar 1 of the OECD



tax rules require multinationals including

"Even from an international tax policy standpoint, most of unilateral measures

digital companies to pay at least some tax

in the markets they interact with.

undertaken by governments around the globe in last several years to deal with growing tax challenges of digitalisation of economies have to be steadily wound back, to make way for uniform tax rules under two pillar solutions espoused by OECD," says Sumit Singhania, Partner, Deloitte India. The other major change

proposed by the amendment in the Finance Bill is a clarification which says where 25% presumptive income regime for electronics manufacturing is available, exemptions under Sections 44DA and 115A will not apply in such cases.

An amendment now empowers the Centralised Processing Centre (CPC) to adjust income tax returns based on inconsistencies with prioryear filings, strengthening the compliance oversight. "By enabling automated checks

for discrepancies, this measure is expected to enhance tax monitoring and reduce instances of tax evasion and misreporting," says Sandeep Jhunjhunwala of Nangia Andersen.

Sensex, Nifty open in green as Flls return on Dalal Street; IT stocks gain

New Delhi. Benchmark stock market indices opened on a positive note on Tuesday, extending their rally for the seventh consecutive session. At the opening bell, the S&P BSE Sensex gained 350 points to open over 78,000, while the NSE Nifty50 gained nearly 100 points to trade above 23,750.

At around 9:25 am, both the indices shed some early gains. The Sensex was trading 177.26 points higher at 78,161.64, while the Nifty50 was trading 55.20 points higher at 23,697.30. Broader market indices were also mixed in early trade, signalling that some investors may be booking profits after the recent rally.

Most of the Nifty sectoral indices came under pressure after opening higher, with the IT index being the only exception. The Nifty IT index was up 1.15%, with shares of TCS, Infosys, HCLTech and Wipro rising over 1%. The jump in IT stocks is one of the biggest factors behind the early morning gains on Dalal Street as all other sectors seem to be under pressure.On the other hand, the top

losers on the Nifty50 were Dr Reddy's, Hindalco, Shriram Finance, IndusInd Bank and Bajaj Auto. Given the early trends, the benchmark indices could witness volatility during intraday trade. However, analysts have turned bullish



about the stock market due to several positive factors, including optimism over strong earnings performance in Q4FY25. The only concern that remains is uncertainty over US reciprocal tariffs.Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said, "The 5.6% rally in the Nifty from the recent lows has been driven by a combination of factors like FIIs turning buyers (Rs 13,765 crores in the last three days), the consequent short-covering and improving macros of the Indian economy.""The surge in mid-and smallcaps has brought the retail

investors aggressively back into the market. Even though the market momentum favours the bulls there is no fundamental support to take the market much higher from the present levels, particularly when President Trump's Damocles sword of reciprocal tariff is hanging over the head of markets," he added."IT has been underperforming on fears of US growth slowdown impacting the Indian IT industry. The

risk-reward in IT stocks is now favourable for buyers. Trump's latest message that he will be "flexible" on tariffs and will "give breaks to many countries" has aroused hopes on some softer treatment to India. But we will have to wait till April 2nd, Vijayakumar explained.

Advance Tax on Property Sale Before March 31, 2025: A Complete Guide

New Delhi. If you are selling a property, for example a residential flat before March 31, 2025, then you will have to pay capital gains tax in the form of advance tax by the last day of the current month. In this article, let's understand how the tax will be structured. If an individual sells property in the upcoming financial year, i.e., 2025-26, then let's see how the seller would pay the advance tax.

Capital gains tax and advance tax rules

f a person (below 60 years of age) is selling a flat in March 2025 and its payment will be made in installments – For example, the first installment will be received in March 2024-25, the second installment after the change of financial year i.e. in April 2025-26, then advance tax rules will be applicable on the individual.

Property sale: What is the rule for advance tax payment of the tax liability in a financial year is more than Rs 10,000, then it is mandatory for the taxpayer to pay advance tax. Let's see when does it have to be paid:y 15 June: Up to 15% payment

By 15 September: Up to 45% payment

By 15 December: Up to 75% payment

By 15 March: 100% payment

Capital gains tax is required to be paid in the same financial year in which the property is transferred,



INR vs Dollar: Rupee recovers 2025 losses; FIIs tiptoe back into Indian market

New Delhi. Rising for the seventh straight session, the rupee appreciated 37 paise to close at 85.61 against the US dollar on Monday, wiping off all its losses in 2025, supported by a positive The local currency hit its record low of trend in domestic equity markets and fresh foreign capital inflows.Besides, lower global crude price levels and continuing weakness in the greenback also bolstered sentiments, traders said. However, lurking risks — ranging from liquidity constraints to reciprocal tariff implementations — continue to pose challenges for the local unit, they added.At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 85.93, then touched an intraday high of 85.49 and a low of 86.01 against the greenback. The unit ended the session at 85.61, registering a gain of 37 paise from its previous closing level. On Friday, the rupee appreciated 38 paise to close at 85.98 against the US dollar.

This is the seventh straight session of gain for the rupee, during which it has added 154 paise. The local unit has recovered all its losses for 2025. On December 31, 2024, the rupee closed at 85.64 against the greenback.

87.59 against the US dollar last month. "The Indian rupee recouped yearly losses as foreign banks and exporters sold the dollars ahead of the financial year-end adjustment, while state-level banks remained aside from buying amid the RBI's USD/INR swap," Dilip Parmar, Research Analyst, HDFC Securities, said.Parmar further noted that the sentiments turned positive ahead of the US representative visiting India ahead of April 2, reciprocal tariff implementations. Moreover, the foreign funds buying in domestic equities also well supported the rupee. In the near term, the spot USD/INR is having support at 85.20 and resistance at 86.05, he noted. Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket

of six currencies, was trading 0.09 per cent lower at 103.99. Brent crude, the global oil benchmark, rose 0.54 per cent to USD 72.55 per barrel in futures trade.In the domestic equity market, the 30-share BSE Sensex surged 1078.87 points, or 1.40 per cent, to settle at 77,984.38, while the Nifty advanced 307.95 points, or 1.32 per cent, to close at 23,658.35 points. Foreign institutional investors (FIIs) purchased equities worth Rs 3,055.76 crore on a net basis on Monday, a c c o r d i n g t o e x c h a n g e data. Meanwhile, India's forex reserves increased by USD 305 million to USD 654.271 billion during the week ended March 14, the RBI said on Friday. In the previous reporting week, the overall reserves rose by USD 15.267 billion to USD 653.966 billion and registered the sharpest weekly rise in two years. The spike in foreign reserves was partly attributed to the USD 10 billion forex swap done by the Reserve Bank of India.

even if the payment is received later.

Date of property transfer

There is no clear rule as to when the property needs to be transferred when the selling is done. There are different rules in parts of the country related to the date of transfer - Some consider the date of agreement as the date of transfer, some record the date of sale deed, some consider the date of registration and some the date of handing over the actual possession of the property. Deadline for paying advance taxIf the official date recorded for the transfer of property is March 15, 2025, then the advance tax will have to be paid by March 15 in 2024-25 itself. If the sale takes place between March 16 and March 31, 2025, then the entire advance tax will have to be paid by March 31, 2025. If the official records state that the property is transferred in FY 2025-26, then capital gains tax will also have to be paid as per the advance tax

India likely to remove 6% Google tax from April 1, tech giants to benefit

NEW DELHI. India is likely to remove the "Google tax," on online advertising services provided by foreign tech companies like Google and Meta. The tax will be scrapped from April 1, 2025, as part of amendments to the Finance Bill, reported news agency Reuters.

This move comes amid efforts to improve trade relations with the US, which had previously criticised the levy and threatened retaliatory tariffs. The removal of the tax is expected to benefit tech companies, advertisers, and India's digital economy.

WHAT IS THE GOOGLE TAX?

The Equalisation Levy was introduced in 2016 to tax payments made by Indian businesses to foreign companies for digital advertising services.

It was aimed at ensuring that global tech firms, which earn significant revenue from Indian users but do not have a physical presence in the country, contribute to India's tax system.

Initially set at 6% for online advertising services, the levy was later expanded in 2020 to include a 2% tax on all ecommerce companies with annual

business exceeding Rs 2 crore in India. 6% equalisation levy, often called the The 2% levy was withdrawn last year following an agreement between India and the US. Now, the government plans to

remove the original 6% tax as well. WHY IS THE GOVERNMENT **REMOVINGIT?**

The decision to remove the tax is part of India's negotiations with the US to avoid trade conflicts. In the past, the US had threatened to impose tariffs of up to 25% on Indian products such as shrimp, basmati rice, and jewellery in response to the equalisation levy. Experts believe the tax removal will help improve India-US relations and prevent any future trade disputes. Some countries, including the UK, are also considering withdrawing similar digital taxes to avoid tensions with the US."Removal of the equalisation levy is a smart move by the government, as collections weren't very high, and it was a concern for the US administration," Sudhir Kapadia, senior advisor at EY told Reuters.HOW WILL TECH GIANTS BENEFIT?

The removal of the Google tax is expected to provide multiple advantages to global tech firms operating in India:Lower IMPACT ON INDIA'S DIGITAL advertising Costs – With the 6% tax gone, advertising on platforms like Google and The decision to remove the tax is expected Meta will become cheaper for Indian businesses, encouraging more digital ad



spending. Higher profit margins - Tech giants will no longer have to account for the levy in their pricing, improving their profitability. More advertisers on digital platforms - Lower costs could attract more advertisers, boosting revenues for digital platforms.Better trade relations -India's move may prevent the US from imposing retaliatory tariffs, ensuring a stable trade environment for multinational companies.

ECONOMY

to encourage more foreign investment in India's digital sector. By lowering costs

for advertisers, it could also lead to higher spending on online platforms, benefiting businesses that rely on digital marketing.

Additionally, the government proposed removing certain tax exemptions available to foreign tech companies in place of the equalisation levy. This means that while the levy will be scrapped, companies may still be taxed o t h e r under

provisions.CHANGES TO OFFSHORE FUNDS RULES

Apart from scrapping the equalisation levy, the Finance Bill also proposes changes to offshore fund management rules. A key amendment removes the word "indirectly" from a provision that restricted Indian residents from participating in offshore funds. This change is aimed at making it easier for offshore funds to relocate to India.

Shiv Sena's Rahool Kanal hits back at Kunal Kamra, says try to be funny next time

Last week, Kamra referred to Shinde as a "gaddar" (traitor) while performing a parody of a song from the film Dil Toh Pagal Hai at the Habitat Comedy Club.

New Delhi. Hours after comedian Kunal Kamra's response defending his "traitor" jab at Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Shiv Sena worker Rahool Kanal hit back, stating that freedom of speech does not mean talking "crap about a leader on a constitutional post." Taking a jibe at Kamra, the Shiv Sena sarcastically advised him to "try to be funny next time." In a post on X, Kanal wrote, "Come out and face the law. A Shivsainik is also a Mumbaikar, and you very well know that.

When you slip or do a paid activity next time, try to be funny but don't crack bones. Jab substance se neend uthe toh voicemail aur bed se bahar aayege. Burnol bheju? Freedom of speech in the Constitution doesn't give you the freedom to talk crap about a leader or a respected individual on a constitutional post. Rise up and get constructive. Your statement itself says that you want to spoil law and order. The law is above all! Satyameva Jayate!" He concluded his post with the words "paid agent" along with a hashtag.

COMEDIAN REFUSES TO **APOLOGIZE**

Comedian Kunal Kamra has made it clear that he will not apologise for his remark on Eknath Shinde. He also condemned the "senseless" vandalism carried out by Shiv Sena workers at the venue where his show

In a lengthy post on X, Kamra sarcastically stated that for his next show, he might choose a venue that requires urgent demolition. Last week, Kamra referred to Shinde as a "gaddar" (traitor) while



performing a parody of a song from the film Dil Toh Pagal Hai at the Habitat Comedy Club. The remark was a reference to Shinde's 2022 rebellion.

VANDALISM AND LEGALACTION

On Sunday night, Shiv Sena workers and the political party.

vandalised the Habitat Comedy Club in Khar and a hotel where the club is located. Following the incident, Mumbai police have booked Kamra for defamation, further escalating tensions between the comedian

'Brella Was Physically Abused, **Financially Drained'**

New Delhi. "We urged her to return after the incidents of extreme domestic violence, but she told us she couldn't return as she had filed a complaint and there were rules," recalls Satbir Singh, father of 24-year-old Harshita Brella, who was murdered in Corby, UK, recently. The grieving father is fighting for justice from his humble residence in Sadh Nagar, Palam, southwest Delhi, hoping that Harshita's husband, Pankaj Lamba, is given the harshest punishment

"She was as innocent as a kid," says her elder sister, Sonia Dabas, as her voice quivers in sorrow. "She always thought if she was good to others, others would be good to her." Recalling how they were inseparable as siblings, Sonia says, "We never needed a third person. We were engrossed in each other's company." She remembers Harshita as a person 'full of life', enjoying food to shopping on the streets of GK and Sarojini Nagar.

Born and raised in Delhi, Harshita attended Pratibha Vikas Vidyalaya in Dwarka and later pursued Hindi (Hons) at Venkateswara College in Delhi University. After completing her B Ed, she began tutoring students. "Parents often said they won't ever find a teacher like her," Sonia

Despite her wish to pursue teaching, Harshita eventually agreed to marry after a proposal came through relatives. The family agreed too. But little did they know what lay ahead. "We were told Pankaj worked for a good company," her sister recalls. "But later, we discovered he was a security guard, a job he was forced to leave. Then he took up a pizza delivery job," says Sonia. The wedding in Hindu rituals took place on March 21, 2024, at a farmhouse in Bijwasan. A few days later, Pankaj left for the UK, and Harshita joined him a month later in April.

"Initially, Harshita faced some challenges adjusting to the new life but continued to stay positive," recalls her sister. It wasn't until domestic abuse began that she reached out to her family for help. Harshita confided in them, revealing the hardships she was facing.

Singh recalls the call he received from Harshita while she was running on the streets of an unfamiliar country in the middle of the night. "She called me and told me what had happened. She then called one of her colleagues, also an Indian. I asked her to run towards her colleague," he shares, adding, "That night Harshita was thrashed by Pankaj, and when she tried to escape, he chased her down the street, assaulting her and hurling abusive words at her.'

It was then that Harshita approached the authorities for help. She stayed at the colleague's house for a couple of days and then under police protection, as per family members. "She suffered a miscarriage during this time. Harshita was not only physically abused but financially drained. Pankaj regularly took money from her, using various excuses—whether for groceries or friends. When they lived together, he used to make her work extra hours for more money, even on her days off. When she came home, she had to do all the housework. She wasn't even allowed to talk to anyone," recalls Sonia.

After her complaint, Harshita got some relief through a Domestic Violence Protection Order, says Singh, adding in the same breath, "but she couldn't return." The last time Harshita called her family, it was around midnight in India. "She told my mother that she should sleep as they had to attend a wedding the next day," Sonia recalls. Days passed, but Harshita's family could not reach her. Then, on Nov 15, 2024, her father received the news that shattered their world. He recalls: "I got a call from one of the Dwarka police stations and the person said, 'Your daughter has been murdered'. I was alone at home when I came to know of this."

Harshita would have turned 25 on Christmas Day, a date that also marked her birthday, but tragically, she never lived to see it. Her body was found in the boot of a car in East London, four days after her death.

Investigators believe she was strangled by Pankaj on Nov 10, 2024, in Corby, Northamptonshire. The family claims they were being pressured for dowry. "On Sep 14, Pankaj's relatives came to our house and threatened us, demanding more dowry.

38-year-old man shoots self dead with illegal pistol in Delhi

NEW DELHI. A 38-year-old lathe machine operator allegedly shot himself in the head on Monday morning in northwest Delhi's Prem Nagar area, police said. According to cops, Prem Nagar police station received information around 10 am on Monday regarding a probable suicide by a person with a gunshot injury to the

During the preliminary inquiry, it was revealed that deceased Prashant Kaushik shot himself on the right side of his head with an illegal country-made pistol. He was employed as a lathe machine operator, a senior officer said. His family, wife and two children were present in the home at the time of incident, the officer added.

The crime and forensic science laboratory teams have visited the scene. Evidence from the site were also collected. While no suicide note has been recovered, family members have not raised any suspicion till now, police said. The body was sent for post-mortem examination. A case of possession of illegal firearm under the Arms Act is being registered and further probe is on to ascertain the reason behind the incident, police

UP Man Takes Friend's Help To Run Over Wife, Wanted To Marry Her

New Delhi. A man in Uttar Pradesh's Bijnor has been arrested for allegedly killing his wife with the help of his friend as he wanted to marry his sister-in-law, the police said Tuesday. The man, Ankit Kumar, conspired with his friend, Sachin Kumar, to get his wife run over by a car as the couple did not have a child, senior police officer Bharat Sonkar told reporters.

The victim, 30-year-old Kiran, who sustained "critical" injuries in the accident, was declared brought dead by the hospital. Both have been arrested and the car used in the accident has



been seized. Varrating the chain of events, Mr Sonkar said that Ankit filed a complaint on March 8 that his wife had died in a road accident when

he was taking her from his in-laws' house to his residence. He claimed that a car ran over Kiran and fled when he left her on the roadside to refuel his bike at a petrol pump.

Based on his complaint, a case was registered and a probe was ordered, Mr Sonkar said. Upon reviewing footage from CCTV cameras in the areas, the police identified the owner of the car as Sachin, a friend of Ankit. During interrogation, Ankit confessed to the crime and said he was married for five years but did not have any children, and wanted to marry his sister-in-law. He had also asked his sister-in-law to marry him, but she refused as he was married to Kiran, forcing him to hatch her murder plan, the police said.

Brace for ad-venture, Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) to open a portal to past

NEW DELHI. "Many a small thing have been made large by the right kind of advertising," Mark Twain once said. Indeed this timeless wisdom has proved true, etched in the dazzling smiles of celebrities, bold taglines and eyecatching hues of iconic products. Yet, beyond the mere glitter of endorsements lies a trove of forgotten stories. Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) is about to open a portal to the past to transport people through decades of India's advertising heritage.

This special archive opens its doors on March 25 and will illuminate the evolution of Indian consumer culture from the 1950s to the present day. The inaugural compilation is a nostalgic hymn to brand heritage, with each name testifying to campaigns that were imprinted on the collective consciousness. Ashok Kumar's dignified endorsement, the graceful allure of Shashikala, Nimmi and Waheeda Rehman, the magnetic presence of Rajesh Khanna - all these are gateways to eras gone by. The launch event will be a confluence of industry stalwarts, media mavens and advertising aficionados, gathering to dissect and celebrate the transformative power of advertisements. Sachchidanand Joshi, member secretary, IGNCA, and the man behind the project, said, "Advertising deserves recognition as an artistic expression. Unlike cartoons where the artist's brushstrokes are evident, advertisements often mask the creators behind layers of brand narratives."

Kunal Kamra case is different, demolition of my home was illegal: Kangana Ranaut

Kangana Ranaut was referring to the demolition of her property in Pali Hill, Bandra, in September 2020, by the BMC on grounds of unauthorised construction.

New Delhi. BJP MP and actor Kangana Ranaut backed the demolition by the Mumbai civic body at the studio where comedian Kunal Kamra made controversial remarks against Eknath Shinde, while underscoring that it should not be compared to the "illegal" razing of her residence in 2020.

"What happened to me (demolition of her bungalow) was an illegal act, but On Sunday night, Shiv Sena workers the actions taken against Kunal Kamra are lawful. There is no comparison between my case and Kamra's case," Ranaut told reporters.

The Mandi MP was referring to the demolition of her property in Pali Hill, Bandra, in September 2020, by the BMC on grounds of unauthorised construction. She had not joined the BJP then and the incident came amid a conflict with the then undivided Shiv

'WHAT CREDENTIALS DOES KUNALKAMRAHAVE?

Kamra kicked up a row last week after he referred to Shinde as a "gaddar" (traitor) while performing a parody of a Bollywood song at the Habitat Comedy Club. The jab was a reference to Shinde's rebellion in 2022, which split the Shiv Sena.

damaged the Habitat Comedy Club in Khar as well as the Unicontinental Hotel, in whose premises the club is located. On Monday, officials from the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) razed a temporary shed with hammers.

Ranaut stressed that criticising Shinde in the name of comedy was an insult to his work and struggles. The first-time BJP MP said Shinde, who once drove an auto for a living, rose to become the Chief Minister through hard work and dedication. "What credentials does Kunal Kamra have? He hasn't achieved anything significant in life," she said. The 'Queen' star said a similar trend was being seen in Bollywood where people are insulting actors under the guise of humour and entertainment.

These people call themselves influencers. Where is society headed for this 2-minute fame? We need to think about this. There could be repercussions. Would you stand by that when you are questioned legally?"

Amid calls by BJP leaders to issue an apology, including by Chief Minister Devendra Fadnavis, Kamra said he won't be cowered. He also slammed the "senseless" vandalism at the studio where his show was held.

Delhi CM Rekha Gupta presents BJP government's maiden budget with 10 focus points

The CM, who also holds the portfolio of finance minister, said that capital expenditure has been increased to about Rs 28,000 crore this year, adding that it was around Rs 15,000 crore last year.



NEW DELHI. Presenting the maiden budget of the newly formed BJP government in Delhi, Chief Minister Rekha Gupta said the government has 10 focus areas, including infrastructure development, water, The CM, who also holds the portfolio of

electricity, and the development of roads. The budget session of the Delhi Assembly, which began on Monday, will see voting on the budget take place on March 27.

finance minister, said that the capital expenditure has been increased to about Rs 28,000 crore this year, adding that the capital expenditure last year was around Rs 15,000 crore.

She said the budget for the financial year

2025-26 will be Rs 1 lakh crore, which is over 31.5 per cent higher than last year's. She called it "a historic budget". The Delhi government has allocated Rs 100 crore in the budget to establish 100 Atal Canteens across the city, and Rs 696 crore has been set aside for development in slum clusters. CM Rekha Gupta announced a Rs 1,000 crore allocation in the FY26 Budget to enhance Delhi-NCR connectivity. She also allocated Rs 5,100 crore for providing Rs 2,500 per month to eligible women and proposed Rs 2,144 crore for the PM Jan Arogya Yojana.

Delhi ramps up desilting efforts as monsoon draws near

The New Delhi Municipal Council (NDMC) has launched a pilot project to use drones and robotic equipment to desilt a 200-metre covered drain near Dayal Singh College.

NEW DELHI. With just three months to go before the onset of monsoon, civic authorities in the capital are ramping up efforts to desilt the city's drains in order to mitigate urban flooding. Authorities plan on using advanced technology, enforcing stricter accountability measures and introducing long-term strategies for effective drainage maintenance. The New Delhi Municipal Council (NDMC) has launched a pilot

project to desilt a 200-metre covered drain near Dayal Singh College using drones and robotic equipment. The site is inaccessible to traditional machinery, making it difficult to assess silt buildup. The Rs 1.7 crore project's tender will open on March 24, with work set for completion by June 30. NDMC has also identified 27 flood-prone areas, including Connaught Place, AIIMS flyover, and Lodhi Colony, where rainwater harvesting systems will be installed. Meanwhile, Public Works Department

(PWD) Minister Parvesh Verma has cracked down on officials failing to maintain drainage systems, suspending an engineer over poor desilting near Akshardham Temple. "Officials have become thick-skinned over the past 10 field to do their jobs," Verma said. He mandated daily road and drainage inspections by PWD engineers, with Last week, Chief Minister Rekha Gupta reports submitted via the PWD e- and Lieutenant-Governor V.K. Saxena



monitoring app. The PWD has also issued fresh guidelines requiring longterm contracts for drain desilting to ensure biannual cleaning. Several measures include levelling and numbering manhole covers, monitoring inter-mixing points where sewage enters storm water drains, and ensuring that desilted waste does not re-enter drains.

costs for accidents caused by desilting negligence.

inspected desilting work at the Sunehri Pul drain after the National Green Tribunal (NGT) flagged delays. The NGT has been hearing multiple pleas from residents across Delhi regarding stormwater drains contaminated with sewage, contributing to foul smells, waterlogging, and Yamuna pollution. To address this, PWD is strengthening coordination with agencies like CPWD and NBCC.

The Irrigation and Flood Control (I&FC) Department of the Delhi government has assured the tribunal that 23 of Delhi's 24 major drains would be desilted by May 31, 2025. However, the Najafgarh drain, the city's largest, will take longer, with a deadline of June 2027.

Various measures taken for desilting purpose

years. They will be made to sweat in the Contractors will now bear compensation Measures include levelling and numbering manhole covers, monitoring intermixing points where sewage enters storm water drains, and ensuring that desilted waste does not re-enter drains.

Attacker rams car into soldier and stabs him, kills elderly man in Israel

Yokneam Illit, Israel. One man was killed and another wounded in a combined ramming, stabbing and shooting attack by a lone assailant at a bus stop in northern Israel on Monday, emergency services said. Police said that the assailant was a 25-year-old Israeli citizen from the country's Arab minority. He rammed his car into an Israeli soldier standing at the bus stop, then got out of his car, stabbed him and seized his weapon. After that, the assailant started shooting at motorists driving past. An 85-year-old man was killed by the gunfire at his car, police said. Israel's ambulance service pronounced him dead at the scene. The soldier was badly wounded and taken to hospital, it said. Police officers shot the assailant dead, a spokesperson said. He resided in a town near the site of the attack, police said in a statement.

US accuses Palestinian student of hiding UN aid agency work on visa application

world. The US government has alleged that Columbia University student and pro-Palestinian demonstrator Mahmoud Khalil withheld that he worked for a United Nations Palestinian relief agency in his visa application, saying that should be grounds for deportation. The UN agency known as UNRWA provides food and healthcare to Palestinian refugees and has become a flashpoint in the Israeli war in Gaza. Israel contends that 12 UNRWA employees were involved in Hamas' attack on Israel on October 7, 2023, leading the US to halt funding of the group. The administration of US President Donald Trump on March 8 detained Khalil, a prominent figure in the pro-Palestinian protests that rocked Columbia's New York City campus last year, and sent him to Louisiana in an attempt to remove him from the country.

The case has drawn attention as a test of free speech rights, with supporters of Khalil saying he was targeted for publicly disagreeing with US policy on Israel and its occupation of Gaza. Khalil has called himself a political prisoner. The US alleges Khalil's presence or activities in the country would have serious foreign policy consequences. A judge has ordered Khalil not be deported while his lawsuit challenging his detention, known as a habeas petition, is heard in another federal court.Khalil, a native of Syria and citizen of Algeria, entered the US on a student visa in 2022 and later filed to become a permanent resident in 2024. In a court brief dated Sunday, the US government outlined its arguments for keeping Khalil in custody while his removal



proceedings continue, arguing first that the US District Court in New Jersey, where the habeas case is being heard, lacks jurisdiction. The brief also says Khalil "withheld membership in certain organisations" which should be grounds for his

UN to reduce staff in Gaza after Israeli strike kills employee

DEIR AL-BALAH. The United Nations said Monday it will "reduce its footprint" in the Gaza Strip after an Israeli tank strike hit one of its compounds last week. killing one staffer from Bulgaria and wounding five other employees. The world body will temporarily remove about a third of its approximately 100 international staffers working in Gaza, UN Secretary-General spokesman Stéphane Dujarric.

He pointed to the increased danger after Israel relaunched its military campaign last week with bombardment that has since killed hundreds of Palestinians. Israel has also cut off all food, medicine. aid and other supplies to Gaza's population for the past three weeks. Dujarric's statement was the UN's first to point the finger at Israel in the March 19 explosion at the UN guesthouse in central Gaza. He said that "based on the information currently available," the strikes on the site "were caused by an Israeli tank."The Israeli military repeated its denial that it was responsible for the strike, which took place a day after Israel shattered Gaza's 2-month-old ceasefire with a surprise bombardment across the Gaza Strip.Dujarric said the UN "has made taken the difficult decision to reduce the Organization's footprint in Gaza, even as humanitarian needs soar."

He said the UN "is not leaving Gaza," pointing out that it still has about 13,000 national staff in Gaza, mainly working for UNRWA, the UN agency for Palestinian refugees. The UN reduction comes as aid workers and medical staff have come under fire. The International Committee of the Red Cross said its office in the southern city of Rafah in the Gaza Strip was damaged by an explosive projectile Monday. It said no staff were hurt but the damage has a direct impact on its ability to operate. It did not specify who was behind the explosion.ICRC also said that on Sunday, contact was lost with emergency medical technicians from the Palestine Red Crescent Society and their whereabouts remain unknown. Last week, humanitarian workers in Gaza were killed and injured, it said.

US, Russia discuss proposed Black Sea ceasefire: Positive announcement likely

up day-long talks on Monday focused on a narrow proposal for a ceasefire at sea between Kyiv and Moscow, part of a diplomatic effort that Washington hopes will help pave the way for broader peace negotiations.

Even as the meeting was under way in Saudi Arabia, where a Ukrainian delegation was present on the sidelines, a Russian missile strike damaged a school and a hospital in Ukraine, wounding at least 88 people. The talks, which focused, amongst other issues, on trying to reach a Black Sea maritime ceasefire deal, were portrayed by Washington as a step in President Donald Trump's effort to end the three-year-old war.A White House source said progress was being made in the Riyadh talks and that a "positive announcement" was expected "in the near future." Russia's RIA news agency said the Russian delegation, when asked about their mood after the end of the talks, replied: "It's good." A Russian source told Reuters that the talks had concluded late on Monday and a draft joint statement

had been sent to Moscow and Washington for approval, with the parties aiming to release it on Tuesday. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said earlier that no documents would be signed, the TASS agency reported. Earlier on Monday, Trump listed other issues he said were on the table: "We're talking about territory right now. We're talking about lines of demarcation, talking about power, power plant ownership."Last week, Russia rejected a proposal by Trump for a full 30-day ceasefire in Ukraine, and it has so far agreed only to a moratorium on attacking energy infrastructure. As Monday's talks were being held in Riyadh, Russian missiles struck the city of Sumy in northeastern Ukraine. Several high-rise residential blocks were damaged along with a school and hospital, regional governor Volodymyr Artiukh said in a video filmed in front of a blaze producing a column of smoke. The schoolchildren were in a shelter at the time, averting worse casualties, he

carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities," Ukrainian foreign minister Andrii Sybiha said."Instead of



making hollow statements about peace, Russia must stop bombing our cities and end its war on civilians.'

The talks in Saudi Arabia follow phone calls last week between Trump and the two

MARITIME TRUCE?

Ukraine and Vladimir Putin of Russia. Ukrainian officials met the Americans in Saudi Arabia on Sunday. Trump, who has

scaled back US diplomatic backing for Ukraine and shifted publicly to a stance far less critical of Russia than that of his predecessor Joe Biden, says he aims to bring a quick end to the war.

The White House says the initial aim of the Saudi talks is to secure a maritime truce in the Black Sea, allowing the free flow of shipping.But maritime battles have been a comparatively limited facet of the war since 2023, after Ukrainian attacks drove Moscow to move its navy far from contested waters, making it possible for Ukraine to reopen ports and resume exports.

"This is primarily about the safety of navigation," Kremlin spokesperson Peskov said. He said a previous U.N.-backed agreement on Black Sea shipping had failed

I know nothing: Trump on US officials mistakenly sharing war plan with journalist

War plan had details on weapons, targets, and timing Group chat included The Atlantic's editor, who disclosed incident White House confirmed the misstep, reviewing how it happened

world. US President Donald Trump's top national security officials, including his Defence Secretary, mistakenly shared war plans for upcoming military strikes in Yemen in a group chat on a secure messaging app that included the editor-in-chief of The Atlantic magazine, the White House said on Monday after the magazine disclosed the incident.

According to The Atlantic's Jeffrey Goldberg, the plan, which included precise information about weapons packages, targets, and timing, was

shared in the group chat two hours before the US launched an attack in Yemen on March 15. The world found out shortly before 2 pm Eastern Time on March 15 that the United States was bombing Houthi targets across Yemen. However, I knew two hours before the first bombs exploded that the attack might be coming. The



reason I knew this is that Pete Hegseth, the Secretary of Defence, had texted me the war plan at 11.44 am. The plan included precise information about weapons packages, targets, and timing," the first-hand report by the magazine said. The US National Security Council spokesperson, Brian Hughes, acknowledged the misstep and said the chat group appeared to be

President JD Vance, US Secretary of State Marco Rubio, CIA Director John Ratcliffe, Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, Treasury Secretary Scott Bessent, White House Chief of Staff Susie Wiles, and senior National Security Council officials were also part of the chat group, according to Goldberg. At this time, the

message thread that was reported appears to be authentic, and we are reviewing how an inadvertent number was added to the chain. The thread is a demonstration of the deep and thoughtful policy coordination between senior officials. The ongoing success of the Houthi operation demonstrates that there were no threats to our service members or our national security,' the National Security Council spokesperson's statement said.

Defense Secretary Pete Hegseth denied the texts to reporters, "You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again...This is a guy who peddles in garbage...Nobody was texting war plans and that's all I have to

China likely to, India has intent to interfere in elections: Canada spy agency

world. Canada's spy agency claimed on Monday that India and China are likely to attempt interference in the upcoming Canadian general election on April 28, while Russia and Pakistan also have the potential to do so, news agency Reuters reported.

The Canadian Security Intelligence Service (CSIS) made these remarks at a time when Ottawa's ties with New Delhi are at an all-time low due to Canada's perceived inaction against anti-India elements and Khalistani supporters operating on its soil, along with allegations of India's involvement in the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar.India has previously denied the allegations of interference, while China has also issued a similar denial.Canadian Security Intelligence Service deputy director, Vanessa Lloyd, said that hostile state actors were increasingly leveraging artificial intelligence to meddle in elections. 'The PRC (People's Republic of China) is highly likely to use AI-enabled tools to attempt to interfere with Canada's democratic process in this current election," Reuters quoted Lyod as saying. She added, "We have also seen that the government of India has the intent and



US airstrikes targeting Yemen's Houthi rebels kill at least two people, group says

The American strikes on the rebels, who threaten maritime trade and Israel, entered their 10th day without any sign of stopping.

DUBAI. U.S. airstrikes targeting Yemen's Houthi rebels pounded sites across the country into early Tuesday, with the group saying one attack in the capital killed at least two people and wounded more than a dozen others.

The American strikes on the rebels, who threaten maritime trade and Israel, entered their 10th day without any sign of stopping. They are part of a campaign by U.S. President Donald



Trump targeting the rebel group while also trying to pressure Iran, the Houthis' main benefactor. So far, the U.S. has not offered any specifics on the sites it is striking, though Trump's national security adviser Mike Waltz claimed the attacks have "taken out key Houthi leadership, including their head missileer."That's something so far that's not been acknowledged by the Houthis, though the rebels have downplayed their losses in the past and exaggerated their attacks attempting to target American warships."We've hit their headquarters," Waltz told CBS' "Face the Nation" on Sunday. "We've hit communications nodes, weapons factories and even some of their over-the-water drone production facilities."An apparent U.S. strike Sunday hit a building in

a western neighborhood of Yemen's capital, Sanaa, killing at least two people and wounding 13 others, the rebel-controlled SABA news agency said, citing health officials. Footage released by the rebels showed the rubble of a collapsed building and pools of blood staining the gray dust covering the ground. A building next to the collapsed structure still stood, suggesting American forces likely used a lower-yield warhead in the strike.

capability to interfere in Canadian communities and democratic processes". An official probe report released in January claimed that Canada was slow to respond to interference attempts by China and India during the 2019 and 2021 elections, although the meddling did not affect the outcomes.

Relations between Canada and India have witnessed an unprecedented diplomatic standoff in recent months, with both countries expelling multiple diplomats, including the respective heads of mission, following allegations of India's involvement in a plot against Sikh separatists on Canadian soil. The Chinese and Indian diplomatic missions in Ottawa have not yet responded to Canada's allegations. Canada is set to hold its general election on April 28 after newly appointed Prime Minister Mark Carney called a snap poll, citing the need for a strong mandate to address the challenges posed by US President Donald Trump.

Nazis had more rights to contest deportation than Venezuelan migrants: US Judge

Washington. A US appeals court judge said on Monday that Nazis were given more rights to contest their removal from the United States during World War Two than Venezuelan migrants deported by the Trump administration.

In a contentious hearing, US Circuit Judge Patricia Millett questioned government lawyer Drew Ensign on whether Venezuelans targeted for removal under a little-used 18th-century law had time to contest the Trump administration's assertion that they were members of the Tren de Aragua gang before they were put on planes and deported to El Salvador."Nazis got better treatment under the Alien Enemies Act than has happened here," Millett said, to which Ensign responded, "We certainly dispute the Nazi analogy." Prior to the Trump administration's invocation of the 1798 Alien Enemies Act, the law had been used three times in US history, most recently to

intern and remove Japanese, German and Italian immigrants during World War Two.The Trump administration was asking the appeals court to halt Washington-based US District Judge James Boasberg's two-week ban, imposed on March 15, on the use of the law to justify deportation of alleged Tren de Aragua members without final removal orders from immigration judges. Family members of many of the deported Venezuelan migrants deny the alleged gang ties. Lawyers for one of

the deportees, a Venezuelan professional soccer player and youth coach, said US officials had wrongly labelled him a gang member based on a tattoo of a crown meant to reference his favourite team, Real Madrid. Millett, an appointee of Democratic President Barack Obama, is one of three judges on a panel of the US Court of Appeals for the D.C. Circuit hearing the government's challenge to



Boasberg's order. US Circuit Judge Justin Walker, who was appointed by Republican Donald Trump during his first term as president, appeared more supportive of the government's arguments. The third judge on the panel, Karen Henderson, was appointed by Republican President George H.W. Bush. The court did not say when it would rule. The case has emerged as a major test of Trump's sweeping assertion of

executive power. With Republicans holding a majority in both the House of Representatives and Senate and largely falling in line behind the president's agenda, federal judges have often emerged as the only constraint on Trump's wave of executive actions.In a Monday court filing, government lawyers told Boasberg that they would not be providing any more information about the deportation flights, invoking the state secrets

privilege. That legal doctrine allows the government to withhold information that might endanger national security during court proceedings. After Boasberg temporarily halted the deportations, Trump called for the judge's impeachment in a process that could lead to his removal. In response, US Supreme Court Chief Justice John Roberts issued a rare statement rebuking Trump and stating that appeals.

Wednesday, 26 March 2025

GT vs PBKS, pitch, weather report IPL 2025: Rain expected in Ahmedabad

New Delhi. Ahmedabad is all set to host its first fixture of the Indian Premier League (IPL) 2025 season as Gujarat Titans (GT) take on a revamped Punjab Kings (PBKS) led by Shreyas Iyer on March 25. While GT aim to put their disappointing 2024 campaign behind them, PBKS will look to kickstart a new era under the guidance of head coach Ricky Ponting and Iyer's leadership.

GT have the home advantage at the Narendra Modi Stadium, but PBKS enter the contest with a wave of excitement surrounding their fresh squad. With ideal weather conditions predicted, fans can expect an uninterrupted contest, where the pitch will play a decisive role in determining the outcome.

GT, captained by Shubman Gill, boast a strong squad featuring the explosive Jos Buttler, Rashid Khan, Glenn Phillips, and a formidable pace attack comprising Mohammed Siraj and Gerald Coetzee. However, they face a formidable PBKS unit,



stacked with match-winners like Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Marco Jansen, and Yuzvendra Chahal. This sets up a thrilling contest between two sides eager to make their mark early in the season.

GT vs PBKS, IPL 2025: Narendra Modi Stadium Pitch Report

The Narendra Modi Stadium is known for its batting-friendly conditions, often producing high-scoring games. The pitch offers reliable bounce, allowing batters to play their shots freely. With an average first-innings score of around 200, the venue has favoured aggressive strokeplay.Fast bowlers can generate movement early on, but as the match progresses, the surface slows down, bringing spinners into play. The dry and hard nature of the pitch ensures a balanced contest, with both batters and bowlers getting opportunities to shine.

GT vs PBKS, IPL 2025: Ahmedabad Weather Report

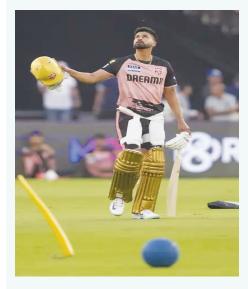
The much-anticipated GT vs PBKS clash will commence at 7:30 PM IST. As per AccuWeather, Ahmedabad is expected to witness clear skies throughout the match, ensuring no rain interruptions.

IPL 2025: Captaincy skills on test as GT host **PBKS** in Ahmedabad

Ahmedabad. Two franchises with refreshed squads, Gujarat Titans and Punjab Kings, aim to start the 18th Indian Premier League (IPL) season positively at the Narendra Modi Stadium on Tuesday, following their disappointing performances last season.

The contest will also showcase a leadership battle between Shubman Gill and Shreyas Iyer, both established Indian ODI players but with uncertain T20I spots. With the Men in Blue eyeing a potential successor to Rohit Sharma, Iyer—having led KKR to IPL glory last year and Mumbai to the Syed Mushtaq Ali title last December—could be a candidate.Go Beyond The Boundary with our YouTube channel. SUBSCRIBE NOW!

Gill, meanwhile, has already been anointed as Rohit's successor, having served as vicecaptain in both Tests and ODIs. However, his T20I credentials are under the scanner. His



IPL record with the Titans has been modest. He replaced Hardik Pandya as skipper last year but managed to win just five games out of 12.Both teams struggled last season, with the Titans finishing eighth and the Kings ninth in the ten-team competition. The Kings are now coached by Aussie great Ricky Ponting, who has already vowed to make the franchise one of the "greatest teams" in the competition. They have a balanced squad to begin with. Their batting lineup is explosive, featuring Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Vishnu Vinod, and Josh Inglis. However, it is their all-round strength that gives the franchise more depth. The Titans will welcome the return of solid left-hander Sai Sudharsan, who is back from surgery.

Sunil Chhetri, Hamza Choudhury in focus as India face Bangladesh

Shillong. How much can one footballer influence the fate of a team or the course of its history? Sunil Chhetri made some good points on that with a strike in his comeback for India vs Maldives in the friendly last week as the hosts returned to winning ways His fellow Spaniard and Indian after over a year of winless results.

And while he and coach Manolo Marquez will look to carry that momentum into the crucial AFC Asian Cup Qualifier against Bangladesh here on Tuesday, their opponents on the day will be eager for the trump card up their sleeve, Hamza Choudhury, to earn their first win against India since 2003.Go Beyond The Boundary with our YouTube channel. SUBSCRIBE NOW!The lead-up to the teams' opening Group C match at JN Stadium here may have been dominated by the hype surrounding two footballers – one, the third highest active scorer in international football after Cristiano Ronaldo and Lionel Messi, and the other, a veteran of 57 Premier League matches for Leicester City. But all 22 players on the pitch will have to play their roles well to churn out three points and take a positive step towards qualification for Saudi Arabia 2027. "I think it's exciting having Hamza and having Sunil back. It's going to be really

competitive. But it's not going to be only about them," Bangladesh coach Javier Cabrera said on Monday. "If we win tomorrow, it will not only be for Hamza."

counterpart Marquez echoed the same feelings for a Chhetriinspired India while also acknowledging the importance of starting the qualifiers on a winning note, with matches against Hong Kong and Singapore to follow thereafter. "The first game is obviously very important. It's a short competition, only the top team qualifies for the tournament. There are six games and we need to

finish first. We want to get the maximum points possible to qualify for Saudi Arabia," he said on match eve on Monday.Already laden with injury woes, the latest being inform Brandon Fernandes against Maldives, it will be interesting to see if Marquez utilises the pace of the young Macarton Nickson or the experience of Udanta Singh — the new inductees into the squad — to make up for Fernandes' absence on Tuesday.He will, however, have been



Bheke, and will hope for them to carry the show vs Bangladesh. However, India have drawn two of their last

three matches against Bangladesh, all of lucky to get away with a point through Adil Khan's late equaliser in their last clash.

down the left, debutant Ayush Dev Chhetri in

midfield, and the aerial prowess of Rahul

While the hosts will be wary of a motivated Bangladesh having Sheffield United's Choudhury making his debut for his national team, it wouldn't be a surprise if Choudhury is pushed further upfield, unlike the deeper midfield role he occupies for his clubs in England, to make a difference with his quality higher up.Also, the partnership that he scripts with skipper and veteran Jamal Bhuyan in the middle could well decide Bangladesh's fortunes in this match and throughout the qualifying campaign.

"We know it's not only Hamza, they have other good players. (And) the same coach for the last three years with the same philosophy. Continuity is obviously important in any team," acknowledged the Indian coach, adding, "But I feel that if we play a good game, we will win this one. But obviously, if you ask Javi Cabrera the same, he will say the opposite."

which came in the Igor Stimac era, and were Tuesday will reveal which Spaniard emerges on top in the South Asian derby or if the cycle of draws between them continues.

Sanjiv Goenka engages in long discussion with Pant after Lucknow's loss

New Delhi. Lucknow Super Giants (LSG) owner Sanjiv Goenka had a long discussion with captain Rishabh Pant following their loss against Delhi Capitals (DC) on Monday, March 24 at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam. Delhi beat Lucknow by one wicket in a thrilling encounter as they chased down the target of 210 and 19.3 overs. Hence, the Axar Patel-led side managed to snatch victory from the jaws of defeat and got their campaign ff to a winning

start. Following Lucknow's loss, owner Sanjiv Goenka had a long discussion with Rishabh Pant and head coach Justin Langer in the team's dugout. The video of the incident has been gaining traction on social media as fans were reminded of Goenka's heated chat with LSG's former captain KL Rahul in the previous season. However, on this occasion, he was having a healthy



discussion with his captain and the coach. Ashutosh Sharma takes Delhi over the lineRishabh Pant had a horrible outing on his debut for Lucknow as he got dismissed for a six-ball duck by Kuldeep Yadav. The 27-year-old also didn't have a memorable day behind the stumps as he missed the match-defining stumping opportunity of Mohit Sharma in the last over which could've sealed the win for his team.In the

first innings, Lucknow were wellplaced to reach a total in excess of 240 as they were 161/2 after 13.2 overs. However, following Pant's dismissal, a well-set Nicholas Pooran (75 off 30) also got dismissed quickly, which triggered a batting collapse for LSG.As a result, they had to settle for a score of 209/8 in their 20 overs. In reply, Delhi got off to a miserable start to their chase, being at 65/5 in 6.4 overs.

However, Ashutosh Sharma walked in at number seven and showed great intent to keep his team in the chase. He got involved in crucial partnerships with Tristan Stubbs (34 off 22) and Vipraj Nigam (39 off 15) and eventually took the team over the finishing line with his match-winning knock of 66* (31). As a result, he was deservedly adjudged Player of the Match in Delhi's thrilling

IPL 2025 first impression: LSG bowling frailties, Pant's blunders raise red flags New Delhi Lucknow Super Giants had a mere

two per cent chance of losing their IPL 2025 opener in Visakhapatnam when Delhi Capitals were reeling at 7 for 3 and later 65 for 5 in their chase of 210. LSG's batters had seemingly done enough to give their inexperienced bowling line-up a cushion on a good batting strip in Delhi's home away from home. Rishabh Pant, their new captain, was chirpy in the middle, and the owners looked pleased in the stands. Yet, in a stunning turn of events, LSG ended up on the losing side, allowing DC to chase the target with three balls to spare. IPL matches are never over until the final ball is bowled. However, when Ashutosh Sharma was joined by debutant Vipraj Nigam at 113 for 6 in the 13th overright after Delhi had lost their power-hitter Tristan Stubbs-the odds still heavily favoured LSG.Pant's emotions in the final overs told the story. From a confident leader, he turned into a dejected figure, seemingly out of answers to Ashutosh Sharma's clean hitting in the death

Delhi needed 94 runs off the last 42 balls. That

It was good score, we could have done basics right: LSG skipper Rishabh Pant

Giants skipper Rishabh Pant felt his bowlers could have done the basics better at the back end as the target of 210 was defendable against a marauding Delhi Capitals who won by one wicket with three balls to spare in their IPL match on Monday. Ashutosh Sharma's unbeaten 66 off 31 balls and Vipraj Nigam's blistering 39 off 15 deliveries orchestrated an improbable comeback for Delhi Capitals as they secured a stunning one-wicket victory over Lucknow Super Giants with three balls to spare in their ÎPL clash on Monday.At one stage, DC were struggling at 113 for 6 in pursuit of a daunting 210-run target, but Ashutosh and Vipraj turned the game on its head with their fearless hitting.Reflecting on the loss, LSG skipper Rishabh Pant felt his bowlers could have executed the basics better in the crucial moments."I think our top-order batters played really well, and it was a pretty good score on this wicket. We got early wickets, but we knew it was a good pitch to bat on. We

VISAKHAPATNAM. Lucknow Super had to keep doing the basics right more to take from this match. often. I think they had a couple of good An ecstatic DC skipper Axar Patel, revelling in partnerships," Pant said at the post-match presentation. He credited DC's middle-order resurgence, particularly Tristan Stubbs, who



laid the foundation for the late assault."One with Stubbs, with Ashutosh, and one with one other guy (Vipraj Nigam). I think he (Nigam) did a pretty good job and took the game away from us. There was enough for the bowlers, but I think we could have done the basics right."We felt the pressure, we are still settling in, but there are a lot of positives

his leadership style, said his tenure would be a rollercoaster ride."Be prepared for it now. It's going to be like this only under my captaincy.

Things will be up and down a little. Now that we have won, people won't complain about why I gave that over to Stubbs (28 runs)."With batters increasingly dominating the format, Axar pointed out that this trend began last year. Don't remember the last time I saw something like this. The way they played in the first six overs, we felt we gave a few too many early on. We dropped some catches as well. It looked like they could score 240, but we pulled things back."Player of the Match Ashutosh dedicated his award to his mentor Shikhar Dhawan and credited Vipraj for keeping the momentum alive."Well played to Vipraj. I asked him to keep hitting. He was very calm under pressure. Want to dedicate this award to my

was when LSG lost control, allowing Ashutosh and the debutant Vipraj to take the game away.

LSG's BOWLING WOES EXPOSED

The fears regarding LSG's bowling composition turned into reality. The franchise had placed its faith in an Indian core for their pace attack, picking last season's sensation Mayank Yadav alongside Avesh Khan and Mohsin Khan at the mega auction. However, injuries derailed their plans, ruling Mayank and Avesh out of the start of the season while Mohsin was replaced by Shardul Thakur, who had gone unsold in the auction. Ironically, in their first game, it was Thakur-roped in as a last-minute replacement-who led a two-man pace attack alongside rookie Prince Yadav. LSG bolstered their bowling unit with spin, entrusting Ravi Bishnoi to spearhead a group that included M Siddharth and Digvesh Rathi, bowler reminiscent of Sunil Narine. Shahbaz Ahmed was picked as the sixth bowling option.

GT vs PBKS Match Preview, IPL 2025: Gill, Gujarat look to take shine off new Punjab

IPL 2025, Gujarat Titans vs Punjab Kings Match Preview: Shubman Gill and his rejuvenated Gujarat Titans side will be aiming to take the shine of the new-look Punjab Kings side as they face off at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.

New Delhi. Gujarat Titans are all set to start their IPL 2025 campaign and welcome a new-look Punjab Kings side to the Narendra How will the new GT fit in? Modi Stadium in Ahmedabad on Tuesday, One of the greatest things Titans as a franchise March 25. PBKS have been the underperformers in IPL for a long period of

time and the start of a new season always feel like the dawn of a new era at the franchise. This time, at least for the sake of the fans, many are hoping it is true. Shreyas Iyer was roped in for big money and so were Yuzvendra Chahal and Arshdeep Singh. Punjab only retained two uncapped players in Shashank Singh and Prabhsimran Singh and this allowed them to splash the cash on stars like Marcus Stoinis, Marco Jansen and Glenn Maxwell and some top young talent. For Gujarat, it was also a reset of sorts while their nucleus remained the same. They went all in for a new-look pace attack as Kagiso Rabada, Mohammed Siraj and Prasidh Krishna but the big signing was that of Jos Buttler. Both teams traded wins last season, with GT winning in Mullanpur and PBKS securing a thriller in Ahmedabad.

has been known for is how seamlessly their squad members would gel. A Wriddhiman Saha at the top would allow Gill to go and construct his innings, while David Miller and insurance policy, Rahul Tewatia, were always there to finish the innings. They had



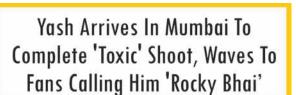
Rashid Khan as their main weapon in bowling, but the likes of Mohammed Shami, Mohit Sharma and Noor Ahmad were key components. Many of those names are now gone and Buttler, Siraj and Krishna have lot to prove after not being retained by their former franchises. The likes of Glenn Phillips and Sherfane Rutherford have been

big performers in white-ball cricket in recent times and Washington Sundar also has a new home.Captain Gill was welcoming towards Buttler and Siraj and showed his support for both men. It now remains to be seen how the

What's Punjab's combination?

Punjab have so many stars amongst them as Ricky Ponting wants to create the greatest PBKS side ever. Well, the names are there but how do they all fit in to the side? Shreyas Iyer has revealed that he plans to play at No.3, something that's justified given his recent exploits.

The opening combination is something that PBKS is yet to reveal or even provide a hint about. Assistant coach Brad Haddin said there are still some talks to be made on who opens."We are not sure who opens yet. We have got guys like Marcus Stoinis and Josh Inglis who have done it well in the past as well. So we have to make sure that we get the right combination.





wo days after announcing the release date of his most-anticipated film Toxic, Yash arrived in Mumbai to complete a schedule of the film. Accompanied by wife Radhika Pandit, the Kannada superstar received a warm welcome from his sea of fans upon arrival in the bay. Yash sported a sharp look with a crisp haircut and well-trimmed beard as he waved at his fans. He wore a comfy co-ord set and sunnies for his airport look. As fans cheered for him and called him Rocky Bhai (his character from KGF), Yash waved and greeted them with folded hands. Take a look at the video here:

On Saturday, March 22, the 'Rocking Star' announced the release date of his upcoming film, Toxic - March 19, 2026. He also treated fans to a brand-new poster from the film. Toxic releases on the Ugadi, Gudi Padwa, and Eid weekend next year. In the poster, the actor wore a black leather jacket and a hat, and carried a gun in his hand. Behind him, was a photo of a whole town burning down and the actor walking away from the site unaffacted. Reportedly, the film might face a major clash from Alia Bhatt, Ranbir Kapoor and Vicky Kaushalstarrer Love & War. An official confirmation from filmmaker Sanjay Leela Bhansali's team is awaited.

Meanwhile, Yash recently surprised fans by making an appearance at Yo Yo Honey Singh's Millionaire India Tour concert in Bengaluru. In a video going viral, Honey introduced Yash, saying, "We have a common story.

When we were sharing with each other, it felt like a true brotherly moment. I have found my moment in Karnataka. Brothers for life, everybody!"Reacting to it, Yash replied, "So inspiring, his story is inspiring, we were discussing, the way he has come up in his life and the place he is today. Everybody goes through struggles and fame, but what matters is the love. People love and respect you. Keep flying."

As for Toxic, the Yash-starrer is directed by Geetu Mohandas. The film also stars Nayanthara, Kiara Advani, Tovino Thomas, Huma Qureshi, Akshay Oberoi, Tara Sutaria, and Darrell D'Silva in strong supporting roles.

Samantha Ruth Prabhu's Latest Video Is Reminder That Women 'Are Stronger Together'



amantha Ruth Prabhu continues to inspire, this time through a powerful three-part campaign titled She Is. Known for her openness about wellness and women's empowerment, the actress uses this series to encourage women to embrace their worth unapologetically.

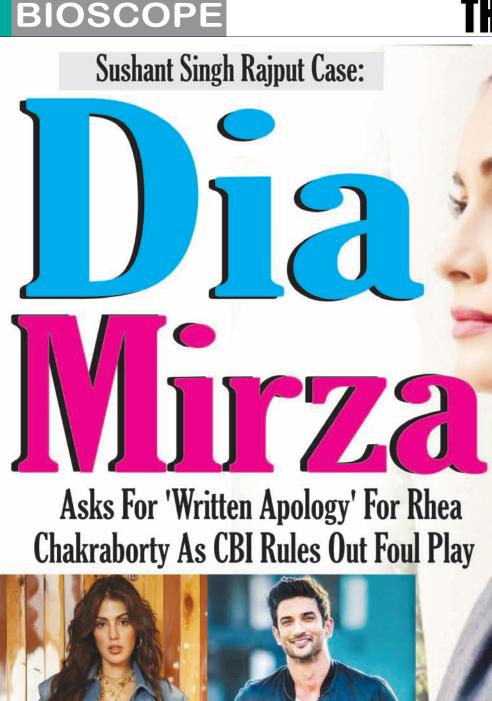
In the latest installment, Samantha is seen pushing her limits - lifting weights, exercising, and radiating strength. But it's not just about physical power. The video carries a deeper message, reminding women to own every part of themselves their beauty, flaws, victories, and scars.

Her voiceover resonates with raw emotion: "She writes not with ink, but with the fire of her will, the power of her heart, and the lessons of her past. With each step, she creates a story — one crafted from strength. She owns her beauty and flaws, her triumphs and scars, knowing her worth, a truth no one can diminish." Sharing the video on Instagram, Samantha wrote, "She Is Strength. Really enjoyed this 3 part series, She Is. We are stronger together. Just a reminder."

It's a bold, heartfelt tribute to the resilience and power that women carry within them — a call to embrace every part of their journey with pride.

In a past interview with GQ India, Samantha Ruth Prabhu spoke about her strong determination to push limits and do things differently. She said, "I think every woman out there is kicking ass with a certain sense of vulnerability, no? No woman is just pretty or just ambitious or just self-sacrificial. She's a combination of several contradictions and complications. Those are the kind of characters I like, the ones that have a little bit of everything. Because I am like that. A lot of people relate to my characters because they see a part of themselves in me."

The actress shared that she has worked hard to feel good about herself and stopped trying to be perfect. In the beginning, she felt a lot of pressure to fit in and get liked by others. She also mentioned that working in the film industry makes it even harder to deal with these feelings. Constantly travelling, staying in different hotels and being away from home can feel very lonely. Through her experiences, the actress has learnt a lot.After appearing in Raj and DK's Citadel: Honey Bunny, Samantha Ruth Prabhu will be seen in Maa Inti Bangaram.



hea Chakraborty, her brother Showik Chakraborty, and their family have been officially cleared by the Central Bureau of Investigation -(CBI) in connection with the death case of actor Sushant Singh Rajput. After years of speculation and intense scrutiny, the agency concluded there was no evidence of foul play in Rajput's tragic death at the age of 34 in his Mumbai apartment in 2020. Back in September 2020, Rhea and Showik were arrested by the Narcotics Control Bureau (NCB) over a drug-related case linked to the late actor's death.

Meanwhile, actress Dia Mirza has reacted to the CBI's closure report and said that the media owes Rhea an apology. Taking to Instagram Stories, she wrote, "Who in the media will have the grace to put out a written apology to Rhea Chakraborthy and her family? You went on a witch hunt. You caused deep anguish and harrasment just for TRP's. Apologise. That's the very least you can do.Rhea's legal counsel, Satish Maneshinde, also weighed in on the development, shedding light on the hardships Rhea and her family endured throughout the investigation. He emphasized that despite no wrongdoing, Rhea spent 27 days in jail before being granted bail. "I salute her and her family for having kept silent and yet suffered the inhuman treatment they were meted," Maneshinde stated. He revealed that Rhea's family had approached him through close friends and defense personnel known from his Sainik School days. He further disclosed how his legal team, alongside Rhea's family, faced relentless threats and harassment but remained steadfast in their pursuit of justice. Maneshinde also strongly opposed the media frenzy around the case. He criticized the false stories spread on social media and news platforms, saying that the lockdown caused more misinformation as people spent more time on their screens with fewer events happening.



Shalini Pandey

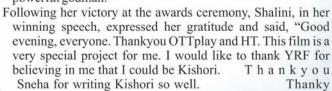
On How To Make Black Look Classy

resh off the success of Dabba Cartel, Shalini Pandey recently delighted fans through a post online. Striking some stellar looks, she exuded beauty in the photos included in the post, leaving fans delighted. A vision in black, Shalini gave a closer view of her looks for an awards night, which was held in Mumbai on March 22. For the star-studded event, she slipped into a breathtaking black outfit, comprising a corset-style top with a long mermaid-style skirt for a look



worth taking notes from. Keeping it minimal, Shalini styled the outfit with silver accessories and sealed the deal with glam makeup and open tresses cascading down her back

Shalini Pandey has carved a niche for herself in the OTT space with her back-to-back power-packed performances in Maharaj and Dabba Cartel. As proof, she recently won the Breakthrough Performance (Female) OTT play award for Maharaj. In the period drama, she essayed Kishori, the love interest of Junaid Khan and a naive follower of a corrupt religious leader. The film also featured Jaideep Ahlawat and Sharvari in the lead roles. Around a fight for justice against a powerful godman.



ou to my co-stars. Recently, Shalini delivered another commendable performance in Dabba Cartel. The show, streaming on Netflix, revolves around the journey of five middle-class women whose business leads them to the dangerous world of drug cartels. It features an ensemble cast of Shabana Azmi, Jyotika, Anjali Anand, Nimisha Sajayan and others. Talking about her experience of working with Azmi in Shabana Azmi."Concluding, Shalini said that working on Dabba Cartel was a

liberating experience.

